वर्ष: 7 अंक: 10

16-30 नवंबर, 2026 (निःशुल्क)

न्यू इंडिया समाचार



12वां संविधान दिवस

विस्मृति से उत्सव तक

26 नवंबर की तारीख जो कभी इतिहास में खो गई थी, वह आज जन-जन का उत्सव है। 12वें संविधान दिवस पर 77 वर्षों की यात्रा, साक्षी है कि 'वी द पीपल' अब केवल प्रस्तावना के शब्द नहीं, बल्कि न्याय, समानता और आत्मनिर्भरता के रूप में 140 करोड़ भारतीयों के जीवन में बना साकार संकल्प...

मन की बात

लोकशक्ति की आराधना



विजयादशमी के पावन अवसर पर 12 वर्ष पहले 'मन की बात' की शुरुआत हुई थी और तब से यह यात्रा निरंतर जारी है। इस यात्रा के सहयात्री भी, और मार्गदर्शक भी देशवासी ही हैं। 'मन की बात' देश के सामान्य मानवी के परिश्रम, पराक्रम, प्रतिबद्धता, समर्पण और सेवाभाव के गौरवगान का शुभ अवसर है। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए 'मन की बात' कार्यक्रम देश के लोगों के प्रयासों को करीब से जानने और उनके योगदान को नमन करने की है एक तीर्थ यात्रा...

- **अनगिनत प्रेरक कहानियां :** 12 वर्षों में देश के हर कोने से ऐसे अनेक लोग सामने आए हैं जिनके असाधारण कार्यों की ओर सामान्य रूप से समाज का ध्यान नहीं जाता। 'मन की बात' ने ऐसी अनगिनत प्रेरक कहानियों को आप सब के सामने लाने का काम किया है।
- **लोकशक्ति की आराधना :** मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तरह से देश की लोकशक्ति की आराधना करता हूं। मुझे इसके माध्यम से देश के हर परिवार से जुड़ने का अवसर मिलता है।
- **खेती विरासत मिशन :** पंजाब में एक प्रयास काफी समय से चल रहा है। यहां 'खेती विरासत मिशन' नाम की एक संस्था ने जैविक खेती और पारंपरिक कृषि के तौर-तरीकों को नया जीवन देना शुरू किया।
- **नया जीवन:** हमारे यहां प्रकृति के प्रति सम्मान की बहुत पुरानी परंपरा रही है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लोगों ने मिलकर एक नदी को नया जीवन देने का प्रयास किया। ये नदी है 'हेवल' (Havel) जिसमें कुछ दिन पहले पानी कम होने लगा था, आसपास के जलस्रोत सूख रहे थे। लोगों ने मिलकर बारिश का पानी रोकने के उपाय किए, बड़ी संख्या में पौधे लगाए। आज नदी को जीवनदान मिला है। साथ ही दर्जनों प्राकृतिक जल-स्रोतों के पुनर्जीवन में भी मदद मिली है।
- **वोकल फॉर लोकल :** त्योहारों के मौसम में सभी ने अपने आसपास एक बदलाव जरूर महसूस किया होगा। अब लोग खरीदारी करते समय स्वदेशी उत्पादों को बहुत महत्व देने लगे हैं। 'वोकल फॉर लोकल' की ये भावना अब हमारे उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा रही है।
- **खादी ग्रामोद्योग :** इस बार गांधी जयंती पर सिर्फ एक दिन में खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री 28 करोड़ रुपये से अधिक की रही। ये पिछले साल से भी डेढ़ करोड़ रुपये ज्यादा है। यानी खादी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है।
- **देशवासियों का विश्वास :** 'ई-संजीवनी योजना' के जरिए अब तक करीब 50 करोड़ टेली-परामर्श किए जा चुके हैं। टेक्नोलॉजी की ताकत, हमारे डॉक्टरों के सेवाभाव और देशवासियों के विश्वास का यह बेहतरीन उदाहरण है।
- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर :** आज देशभर में लगभग 1 लाख 90 हजार आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के जीवन में नई-नई सुविधाएं लेकर आए हैं। ये आरोग्य मंदिर एक प्रकार से, पंचायतों के वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं।
- **असाधारण कार्य :** हमारे युवा आज ऐसे विषयों पर भी काम कर रहे है जो पूरी मानवता का भविष्य बदल सकते है। ऐसी ही एक फील्ड है ब्रेन रिसर्च। इसी से जुड़े, 'सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर' का मैंने आईआईटी मद्रास में लोकार्पण किया था। इस सेंटर ने एक ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म बनाया है। यह दुनिया में अपनी किस्म का पहला मिशन है।
- **महर्षि वाल्मीकि :** हजारों वर्ष बीत गए लेकिन महर्षि वाल्मीकि की रामायण आज भी हमें कुछ नया सिखाती है। उन्होंने हमें जीवन की गहरी सीख दी है। वे हमें निरंतर प्रयास करते रहने एवं सेवा, करुणा और सामाजिक समरसता का महत्व समझाते हैं।
- **अयोध्या में मंदिर :** अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि, निषादराज और माता शबरी के मंदिर भी बनाए गए हैं। मुझे संतोष है कि अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही रखा गया है।

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

न्यू इंडिया
समाचार

वर्ष: 7, अंक: 10 | 16-30 नवंबर, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
सत्यम सिंह
अनिल कुमार



13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

जब 'वी द पीपल' बना जन-जन का उत्सव

12वां संविधान दिवस विशेष

आवरण कथा



देश की आबादी मुश्किल से 36 करोड़ थी, संसाधन सीमित थे और चुनौतियां अनंत... फिर भी संविधान सभा ने अपने अथक परिश्रम से 26 नवंबर 1949 को अमर दस्तावेज राष्ट्र को सौंपा। शायद ही किसी ने तब सोचा होगा कि यह ऐतिहासिक तारीख स्वयं इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस भूली-बिसरी तिथि को पुनर्जीवित कर संविधान दिवस को सचमुच बना दिया जन-जन का उत्सव... | 10-25

राष्ट्रीय एकता दिवस



सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सरदार साहब की भूमिका रही ऐतिहासिक | 8-9

समाचार सार | 4-5

व्यक्तित्व : जगदीश चंद्र बोस
जिन्होंने सिद्ध किया... पौधों में भी होती है जान | 6

मजबूत होती वैश्विक साझेदारी
मुंबई में इंडिया केम 2026 के 14वें संस्करण का आयोजन | 7

पीएम विकसित ग्राम स्वराज व कंटेनर विनिर्माण संवर्धन को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय | 28-29

स्थिरता... अवसर... भविष्य के लिए आशा की नींव
पीएम आवास-ग्रामीण योजना के 10 वर्ष | 30-31

सुरक्षा और गवर्नेंस : सुशासन से संतुलित विकास
आरबीआई के डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन | 32-33

भारत के सामर्थ्य से बढ़ेगा विश्व का सामर्थ्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट-2026 को किया संबोधित | 34-35

विकसित भारत का आधार, वैज्ञानिक अनुसंधान और इनोवेशन
पीएम मोदी ने विज्ञान-नवाचार सम्मेलन का किया उद्घाटन | 36-37

2029 तक निर्मल बनेगी यमुना
दिल्ली में यमुना पुनरुद्धार से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास | 38-39

सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार की किरण
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 11 वर्ष | 40-41

वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन
नमो घाट पर पीएम मोदी वायु सेना दिवस पर कार्यक्रम में हुए शामिल | 42

विजयादशमी



पूरी होगी 'राम से राष्ट्र' और 'देव से देश' की परिकल्पना

विजयादशमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय लिया 'राम से राष्ट्र' और 'देव से देश' का संकल्प हम सब मिलकर जरूर करेंगे पूरा... | 26-27

प्रकाशक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

हम भारत के लोग

संविधान की शक्ति, राष्ट्र की प्रेरणा

सादर नमस्कार

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। यह केवल विधि का ग्रंथ नहीं, बल्कि सभी भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का अमर घोष है। वर्ष 2015 से यह तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जा रही है, जो अब जन-जन का उत्सव बन चुकी है। इस वर्ष 26 नवंबर को इसका 12वां आयोजन हमें स्मरण कराता है कि संविधान की वास्तविक शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि जनजीवन में उतरती उसकी भावना में निहित है।

हमारा संविधान 'हम भारत के लोग' से शुरू होता है। हम ही इसकी ताकत हैं, हम ही प्रेरणा और हम ही इसका उद्देश्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे सरल शब्दों में 'डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया' कहते हैं। यह हमें अधिकारों के प्रति सजग बनाता है और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी।

बीते वर्षों में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' का मंत्र संविधान की भावना की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बनकर सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशन और जनकल्याण की नई गाथा लिख रहा है। जन-धन से आवास तक और आयुष्मान भारत से किसान सम्मान निधि तक, हर पहल समानता और गरिमा के आदर्शों को साकार कर रही है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर संविधान के महत्व को पुनर्स्थापित किया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपसी संतुलन के साथ मजबूत तंत्र के रूप में कार्य कर रही हैं। भारतीय न्याय संहिता सहित नए कानून न्याय व्यवस्था को सरल, आधुनिक और जनोन्मुख बना रहे हैं।

लोकतंत्र की रक्षा सतत जागरूकता से ही संभव है। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन ही संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा है। 'वी द पीपल' केवल प्रस्तावना के शब्द नहीं, राष्ट्रीय जीवन का संकल्प बना है। संविधान की आत्मा को आत्मसात कर विकसित भारत की स्वर्णिम यात्रा में राष्ट्र का हर नागरिक सहभागी बन रहा है। यही इस बार के हमारे विशेष अंक की आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पौधों में भी होती है जान, को सिद्ध करने वाले जगदीश चंद्र बोस, फ्लैगशिप योजना में पीएम आवास-ग्रामीण के 10 वर्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर रेडियो पर प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम मन की बात और बैक कवर पर 22 नवंबर को होने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) दिवस पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपने सुझाव हमें भेजते रहें।

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...





मिलती है सरकार की नवीनतम पहलों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी

मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, सरकार की नवीनतम पहलों, नीतियों, योजनाओं और समसामयिक घटनाओं (करंट अफेयर्स) से अपडेट रहने के लिए नियमित रूप से न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ता हूं। इस शानदार पत्रिका के लिए पूरी टीम को धन्यवाद। मैं इस पत्रिका के नवीनतम और पिछले अंकों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखता हूं।

प्रणव पट्टानी

papattani264@gmail.com

मुझे मिलती है कुछ उपयोगी जानकारी

मेरा नाम चिंतन है। मैं नियमित रूप से 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका पढ़ता हूं। मैं पूरी पत्रिका पर एक नजर डालता हूं। इसमें दी गई जानकारी से मुझे अपने ज्ञान के लिए कुछ उपयोगी बातें मिल जाती हैं।

chintanr390@gmail.com

विकास संबंधी सूचनाओं की मिलती है जानकारी

मैं केंद्र सरकार की आधिकारिक पत्रिका 'न्यू इंडिया समाचार' के तेलुगु संस्करण का नियमित पाठक हूं। मैं सार्वजनिक नीति से जुड़ी जानकारियों को बहुत महत्व देता हूं। मैं 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किए गए विकास के ढांचे, राष्ट्रीय उपलब्धियों और शासन संबंधी विचारों का गहराई से अध्ययन करना चाहता हूं। इसमें यह पत्रिका बहुत सहायक साबित हो रही है।

जी. अशोक

cscashok1399@gmail.com

खुद को अपडेट रखने में बहुत उपयोगी पत्रिका न्यू इंडिया समाचार

मैं 'न्यू इंडिया समाचार' का नियमित पाठक हूं। यह पत्रिका भारत सरकार की योजनाओं, नीतियों और समसामयिक मामलों के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए बहुत उपयोगी लगती है। यह मैगजीन देश की तरक्की के बारे में मेरी जानकारी बढ़ाती है। मुझे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ज्यादा समझने और हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती है।

निवेश गोयल

goyalnivesh98@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in

समाचार सार

एशियाई पैरा खेल 2026 भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन



जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 114 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि पैरा-एथलीटों ने क्या असाधारण उपलब्धि हासिल की है! यह पूरे देश के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का अवसर है! प्रत्येक खिलाड़ी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान दिया है। अपनी उपलब्धियों से अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है।

भारत ने एशियाई पैरा खेल 2022 में 111 पदकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। भारत के पदकों में पैरा एथलेटिक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसने 22 स्वर्ण सहित 65 पदक दिलाए। शीतल देवी तीन पदकों (दो स्वर्ण, एक रजत) के साथ भारत की सबसे सफल एथलीट रहीं।

सुरक्षा चुनौतियों से निपटेगा वाइब्रेंट सिविल डिफेंस नेटवर्क

भारत में वाइब्रेंट सिविल डिफेंस नेटवर्क तैयार करने के लिए भारतीय सेना के साथ विशेष प्रशिक्षण पहल शुरू की जा रही है। पहले चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 सिविल डिफेंस मास्टर ट्रेनर्स को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वाइब्रेंट सिविल डिफेंस नेटवर्क के निर्माण का विजन पेश किया था।



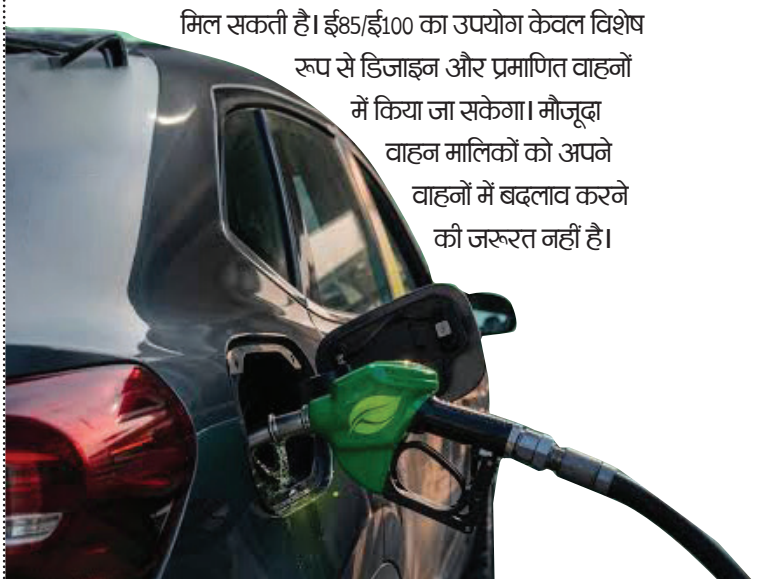


प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से 50 मास्टर ट्रेनर्स इसमें शामिल होंगे। प्रशिक्षण में खतरे के प्रति जागरूकता, सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया, संचार एवं समन्वय पर जोर रहेगा। इसमें आधुनिक और हाइब्रिड युद्ध, ड्रोन व हवाई हमले के खतरे, अग्नि सुरक्षा, खोज एवं बचाव, साइबर स्वच्छता और नागरिक-सैन्य समन्वय जैसे विषय शामिल हैं। प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक मास्टर ट्रेनर 100 सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स को प्रशिक्षित करेगा।

ई85/ई100 ईंधन वाहनों के लिए बदले नियम

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई85 और ई100 फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। पर्यावरण हितैषी इन ईंधनों के लिए प्रमाणित वाहनों को लागू उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। ई85 में आयतन के हिसाब से 85 प्रतिशत तक इथेनॉल होता है।

मंत्रालय के अनुसार, देश में उत्पादित इथेनॉल के अधिक उपयोग से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। ई85/ई100 का उपयोग केवल विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित वाहनों में किया जा सकेगा। मौजूदा वाहन मालिकों को अपने वाहनों में बदलाव करने की जरूरत नहीं है।



'एग्री वेलफेयर पोर्टल' मोबाइल पर खेती-किसानी की जानकारी

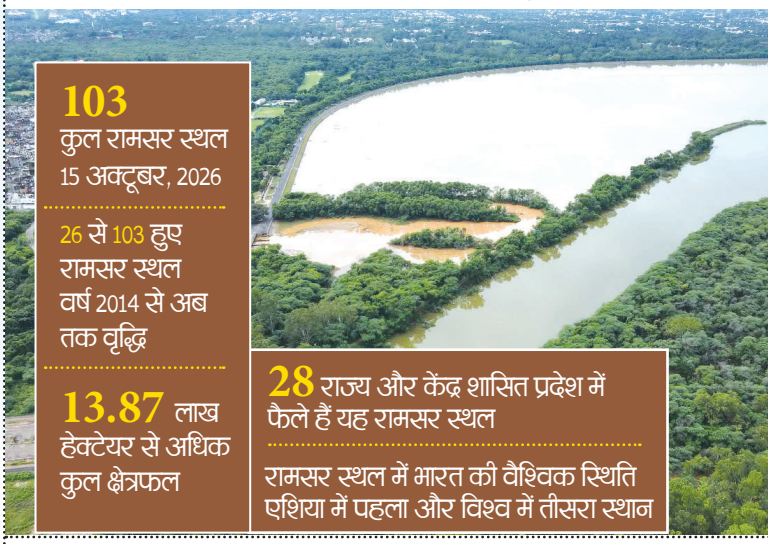
देश के अन्नदाताओं को अब खेती-किसानी और कल्याण से जुड़ी सेवाओं की जानकारी लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब घर बैठे खाद-बीज और योजनाओं की जानकारी मिलेगी। एक ही जगह मंत्रालय की सभी सेवाएं होंगी जिससे अन्नदाता डिजिटली और सशक्त होगा।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए संशोधित 'एग्री वेलफेयर पोर्टल' शुरू किया है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और खेती-किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारियां सीधे किसानों के मोबाइल तक पहुंचाना है। पोर्टल पर मंत्रालय की योजनाओं, सब्सिडी, नियमों और डिजिटल सेवाओं, मौसम, बीज-खाद की उपलब्धता, मंडियों के भाव और वैज्ञानिक खेती की जानकारी मिलेगी। इसे कमजोर इंटरनेट और साधारण स्मार्टफोन पर इस्तेमाल के अनुकूल बनाया गया है।



देश में 103 हुई रामसर स्थलों की संख्या

भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुखना आर्द्रभूमि (चंडीगढ़) और सौज झील (उत्तर प्रदेश) को इस सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की। वर्ष 2014 में भारत में 26 रामसर स्थल थे, जिनकी संख्या अब लगभग चार गुना हो गई है। रामसर स्थल जैव विविधता के संरक्षण, बाढ़ के प्रभाव को कम करने, भूजल पुनर्भरण और आजीविका बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ।



103
कुल रामसर स्थल
15 अक्टूबर, 2026

26 से 103 हुए रामसर स्थल वर्ष 2014 से अब तक वृद्धि

13.87 लाख हेक्टेयर से अधिक कुल क्षेत्रफल

28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैले हैं यह रामसर स्थल

रामसर स्थल में भारत की वैश्विक स्थिति एशिया में पहला और विश्व में तीसरा स्थान

आयुष नवाचार : पेटेंट आवेदन 8 गुना बढ़े

आयुष क्षेत्र में नवाचार और बौद्धिक संपदा गतिविधियों में पिछले एक दशक में तेज बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच आयुष से जुड़े 4,077 पेटेंट आवेदन दायर हुए और 711 पेटेंट प्रदान किए गए। वार्षिक आवेदन 63 से बढ़कर 590 हो गए, यानी करीब 836.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयुष से संबंधित आविष्कारों पर जारी स्थिति रिपोर्ट (2014-2026) में यह जानकारी सामने आई है।

कोविड-19 के बाद के छह वर्षों में 2,854 आवेदन दायर हुए जो कुल आवेदनों का 70 प्रतिशत है। इसी अवधि में 657 पेटेंट प्रदान किए गए। आमजन ने सबसे अधिक 2,113 आवेदन किए, जबकि शैक्षणिक संस्थानों ने 995 आवेदन दायर किए।

...और बढ़ेगी देश की रक्षा क्षमता

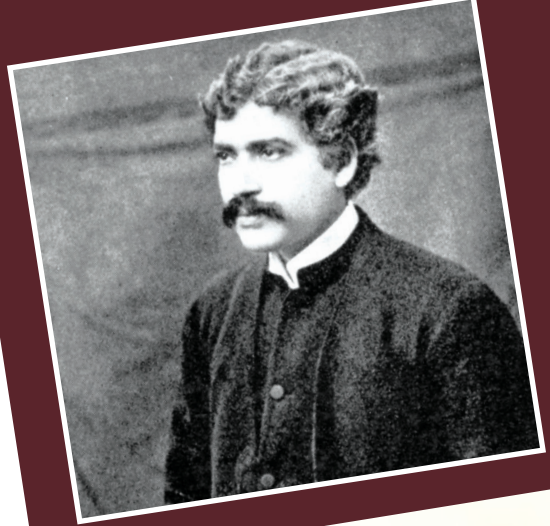
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर 2026 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में रक्षा बलों के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें करीब 82 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योग से होगी, जिससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय सेना के लिए ड्रोन, निगरानी यूएवी, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोन और स्व-चालित गन सिस्टम सहित आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। नौसेना को एंटी-शिप मिसाइलों से रक्षा के लिए आधुनिक प्रणालियां मिलेंगी। वहीं, वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर, वायु रक्षा प्रणाली, हथियार और मौसम रडार मंजूर किए गए हैं। इससे रक्षा बलों की निगरानी, गतिशीलता और मारक क्षमता मजबूत होगी।



जिन्होंने सिद्ध किया...

पौधों में भी होती है जान



जन्म : 30 नवंबर, 1858
मृत्यु : 23 नवंबर, 1937

रेडियो विज्ञान की नींव रखने और पौधों में जीवन-प्रतिक्रियाओं को सिद्ध करने वाले अद्वितीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि पेड़-पौधे भी महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। उनसे करुणा का रिश्ता भी संभव है। वहीं, वायरलेस संचार के क्षेत्र में उनके अग्रणी प्रयोगों ने उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई। खोज और नवाचार की उनकी तपस्या आज भी युवा पीढ़ी के लिए बनी है प्रेरणा...

खेलते-खेलते एक बच्चे ने पेड़ की एक टहनी को जोर से हिलाया और उसके फूल-पत्ते तोड़ने लगा। तभी मां ने बच्चे को समझाया कि अब शाम हो चुकी है। इस समय पेड़-पौधों को मत छुओ। न ही उनके पत्ते तोड़ो। पेड़-पौधे भी हमारी तरह रात को सो जाते हैं। अगर तुम इस समय ऐसा करोगे तो उन्हें बहुत दर्द होगा। बचपन में मां द्वारा कही गई इस बात का बच्चे के मन पर गहरा असर हुआ। मन में यह जिज्ञासा बैठ गई कि क्या वाकई पौधों को भी हमारी तरह दर्द और सुख-दुख का अहसास होता है? उस बच्चे ने बड़े होकर इसी कौतूहल को वैज्ञानिक कसौटी पर परखा। क्रेस्कोग्राफ नामक अत्यंत संवेदनशील यंत्र का आविष्कार किया जिससे पौधों की बहुत धीमी वृद्धि को भी मापा जा सकता था। दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया कि पेड़-पौधों में भी जीवन और चेतना होती है। यह महान वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि जगदीश चंद्र बोस थे। 30 नवंबर 1858 को बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश) के मेमनसिंह गांव में जन्मे जगदीश चंद्र बोस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सुक्ष्म तरंगो की प्रकाशिकी पर कार्य किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, बोस वायरलेस रेडियो प्रसार के सह-खोजकर्ता थे। उन्होंने बहुत छोटी विद्युत-चुंबकीय तरंगें पैदा करने और उन्हें पकड़ने वाले उपकरणों में महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता भी माना जाता है। आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेव गाइड, ध्रुवक, परावैद्युत लेंस, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिये अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का अविष्कार 19वीं सदी के अंतिम दशक में बोस ने किया।

वर्ष 1917 में जगदीश चंद्र बोस को 'नाइटहुड' की उपाधि प्रदान की गई। शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए 'रॉयल सोसायटी लंदन' के फैलो चुन लिए गए। बोस ने अपना पूरा शोधकार्य किसी अच्छे या महंगे उपकरण और प्रयोगशाला से नहीं किया था, इसलिए वह एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। 'बोस इंस्टीट्यूट' (बोस विज्ञान मंदिर) इसी विचार से प्रेरित है। आज यह देश के प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है। उन्होंने कई विषयों पर पुस्तकें भी लिखी हैं। 23 नवंबर, 1937 को जगदीश चंद्र बोस का निधन हो गया।

ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के साथ-साथ जगदीश चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं जिन्होंने कम वेतन के खिलाफ अंग्रेजों का विरोध किया और अपने अधिकार के लिए 'सत्याग्रह' किया था। 25 फरवरी 2018 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर जगदीश चंद्र बोस को भारत का गौरव बताया था। इतना ही नहीं, 4 जनवरी 2021 को उन्होंने कहा था कि जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में माइक्रोवेव के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सर बोस उसके व्यापारिक इस्तेमाल की दिशा में नहीं बढ़े, लेकिन आज रेडियो संचार प्रणाली उसी सिद्धांत पर खड़ा है। ■





इंडिया केम 2026

मजबूत होती वैश्विक साझेदारी

विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए विश्वस्तरीय रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग का मजबूत होना आवश्यक है। यही कारण है कि सरकार देश में रसायन क्षेत्र के लिए सबसे अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में 22 अक्टूबर को मुंबई में इंडिया केम 2026 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। इंडिया केम 2026 का उद्देश्य वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में सतत विकास को देना है बढ़ावा...

वर्ष 2047 तक राष्ट्र, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना चाहता है जिसमें सरकार द्वारा शुरू किए गए तीन नए समर्पित रसायन पार्कों के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंडिया केम 2026 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि कारोबार करना आसान बनाने के प्रयासों और भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के बढ़ते नेटवर्क से निवेश तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय रसायन निर्माता इन अवसरों का लाभ उठाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी मजबूत करेंगे।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने इंडिया केम 2026 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से जापान इस आयोजन का साझेदार देश बना जिससे रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर खुलेंगे।

भारतीय रसायन उद्योग क्षेत्र के विकास की संभावनाएं मजबूत

- भारतीय रसायन उद्योग के वर्ष 2030 तक 300 अरब डॉलर और वर्ष 2040 तक एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- घरेलू मांग में वृद्धि, निर्यात के बढ़ते अवसर, भारत की बड़ी युवा आबादी, प्रति व्यक्ति अपेक्षाकृत कम खपत और सरकार की सहायक पहलों से इस क्षेत्र के विकास की संभावनाएं मजबूत।

आठ हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए

- आयोजन में जापान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देश, लैटिन अमेरिका, दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के प्रतिनिधि शामिल।
- कार्यक्रम में भारत और विदेशों के 200 से अधिक प्रदर्शक, देश-विदेश से आठ हजार से अधिक कारोबारी और 50 प्रमुख भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हुए।

"इंडिया केम 2026 सार्थक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करेगा और ऐसी साझेदारियों का मार्ग प्रशस्त करेगा जो इस क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास में योगदान देंगी। **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

सरदार पटेल ने रखा...

हिमालय से हिंद महासागर तक भारत को सुरक्षित

सरदार पटेल की 151वीं जयंती (एकता दिवस) पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सरदार साहब की भूमिका ऐतिहासिक रही। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक भारत को सुरक्षित रखने के सरदार पटेल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक प्रहार किया है। साथ ही, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुरूप विगत एक दशक में लगभग 50 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर निकले हैं जो नए, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के इस अभूतपूर्व परिवर्तन को करता है प्रमाणित...



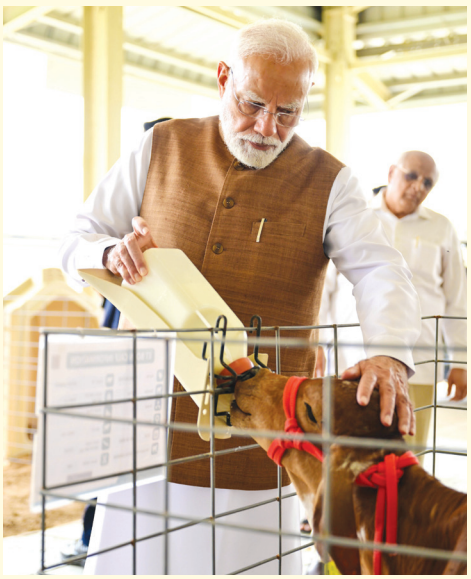
प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

गुजरात के एकता नगर में 31 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा कि स्वतंत्रता किसी राष्ट्र को अपना भविष्य स्वयं तय करने का अधिकार देती है, वहीं एकता पूरे देश को एक साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। यही वजह है कि आज देश में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एकता दिवस, तीनों पर्वों को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। एकता दिवस अब केवल औपचारिक आयोजनों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा जन गौरव का उत्सव बन गया है। सरदार पटेल को एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के वर्तमान भौगोलिक और राजनीतिक स्वरूप को आकार देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

सरदार पटेल ने देश को भौगोलिक और भावनात्मक, दोनों रूपों में एकजुट कर आधुनिक भारत की नींव रखी। राष्ट्र के सांस्कृतिक

बनासकांठा में प्रधानमंत्री

बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर



बनासकांठा के भीलडी में भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (बीआरसी) राष्ट्र को समर्पित किया गया। 127 एकड़ में फैले इस संस्थान को अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। यह कांकरेज मवेशी नस्ल को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला सुविधा केंद्र होगा।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास...

- थराद और राधनपुर में बनास डेयरी के दो बायो-सीएनजी संयंत्रों की आधारशिला, जिनकी मवेशियों के गोबर प्रसंस्करण क्षमता क्रमशः 75 और 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन है।
- अहमदाबाद मेट्रो फेज-2ए (हवाई अड्डा विस्तार) और फेज-2बी (गिफ्ट सिटी विस्तार) की आधारशिला। फेज-2ए की लंबाई 6 किमी से अधिक होगी, जिसमें कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट तक पांच स्टेशन शामिल होंगे, जबकि फेज-2बी की लंबाई 3.3 किमी से अधिक होगी।
- लगभग 2,600 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद-मेहसाणा सड़क (राज्य राजमार्ग-41) को चार लेन से आठ लेन में अपग्रेड और मजबूत करने की आधारशिला।
- 4,030 नए बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला, गुजरात के 361 पूर्ण बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन।
- लगभग 4,950 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष के तहत पूरी की गई 521 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित।
- देश भर के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए 19,000 करोड़ रुपये की पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी।

400 करोड़ रु. की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास...

- एकता नगर में 400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास और उद्घाटन।

पुनर्जागरण की शुरुआत करने में भी सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के माध्यम से उन्होंने देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मार्ग भी प्रशस्त किया। राष्ट्रीय एकता के भव्य आयोजनों, वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद, तेज आर्थिक विकास और काशी विश्वनाथ से लेकर राम मंदिर तक हो रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश आज उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, जिसकी परिकल्पना सरदार पटेल ने की थी।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में दो वर्षों तक चले समारोहों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान देश ने कई महत्वपूर्ण संकल्प लिए थे। उन्होंने सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि देश ने इन संकल्पों को बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इन दो वर्षों में देश ने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो पहले कभी नहीं बने थे।"

पीएम मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके चरणों में ली गई नक्सलवाद और माओवादी आतंक के पूरी तरह समाप्त होने तक चैन से नहीं बैठने वाली उस प्रतिज्ञा को याद करते हुए कहा कि महज एक वर्ष के भीतर वामपंथी उग्रवाद की कमर टूट गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक हिंसा से प्रभावित रहे क्षेत्र अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2024 से पहले के 10-12 वर्षों के दौरान 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। पहले जहां हर 100 में से 27 लोग अत्यधिक गरीबी की चपेट में थे, वहीं आज यह संख्या 3 से भी कम रह गई है। ■

जब 'वी द पीपल' बना जन-जन का उत्सव



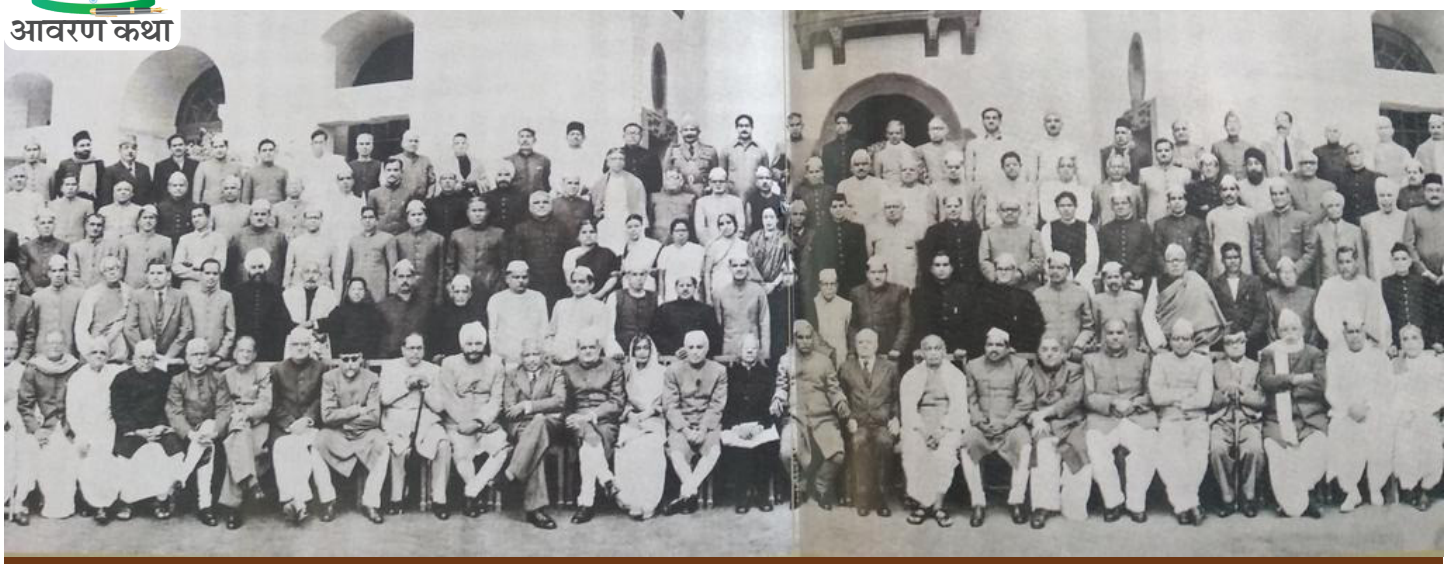
तब देश की आबादी मुश्किल से 36 करोड़ थी, संसाधन सीमित थे और चुनौतियां अनंत... फिर भी संविधान सभा ने अपने अथक परिश्रम से 26 नवंबर 1949 को जो अमर दस्तावेज राष्ट्र को सौंपा, उसने हर भारतवासी के सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं को शब्दों में पिरो दिया। शायद ही किसी ने तब सोचा होगा कि यह ऐतिहासिक तारीख स्वयं इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस भूली-बिसरी तिथि को पुनर्जीवित कर संविधान दिवस को सचमुच जन-जन का उत्सव बना दिया।

इस 26 नवंबर, देश 12वां संविधान दिवस मनाएगा, 77 वर्षों की उस अनवरत यात्रा का उत्सव, जिसमें "वी द पीपल" का आह्वान अब केवल प्रस्तावना के तीन शब्दों तक सीमित नहीं रहा। यह भावना आज हर नए न्याय-कानून की निष्पक्षता में सांस लेती है, हर लाभार्थी के सिर पर बने पक्के छत में जीवंत होती है, किसान के खाते में सीधे उतरती सम्मान राशि में धड़कती है और सरल होते जीएसटी ढांचे में मुस्कुराती है। लोकतंत्र की जननी भारत का यह गौरव आज विश्व मंच पर गूंज रहा है, यही है संकल्प से सिद्धि तक की वह यात्रा जो विकसित भारत की ओर अग्रसर है, जिसके लिए संविधान अब ग्रंथ भर नहीं, बल्कि बन चुकी है 140 करोड़ भारतीयों की सांझी आत्मा...

मानव रचित किसी दस्तावेज को यदि सचमुच अमर कहा जा सकता है तो वह भारत का संविधान है। बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को राष्ट्र का पवित्र ग्रंथ और पथ-प्रदर्शक मानते हुए विकास का ऐसा आधारस्तंभ खड़ा किया है, जिससे देश दशकों तक वंचित रहा। जिन समस्याओं को पहले नियति मानकर राजनेता हाथ लगाने से बचते थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें छुआ भी और समाधान करके भी दिखाया। संविधान अब केवल कानून की किताब नहीं, बल्कि सही अर्थों में एक सामाजिक दस्तावेज बन चुका है। इस 26 नवंबर को देश 12वां संविधान दिवस मना रहा है, संविधान को अंगीकार किए जाने के 77 वर्ष पूर्ण होंगे। ऐसे में बीते एक दशक से अधिक समय में "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण बन गया है।

एक भूली-बिसरी तारीख से राष्ट्रीय उत्सव तक

जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, तो यह ऐतिहासिक दिन दशकों तक इतिहास के पन्नों में दबा रहा। इस तारीख को औपचारिक रूप से "संविधान दिवस" के रूप में मनाने की अधिसूचना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को जारी की। यानी संविधान स्वीकृत होने के 65 वर्ष बाद। यह विचार तब आया जब देश डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं याद दिलाया कि इससे बड़ा पवित्र अवसर और क्या हो सकता था कि जिन्होंने संविधान का नजराना दिया, उन्हें सदा-सदा के लिए स्मरण किया जाए। दिलचस्प यह भी है कि यह पहला अवसर नहीं था, जब संविधान के लिए एक विशेष दिवस को प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया था। इससे पहले वर्ष 2009 में, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य सरकार ने संविधान के 60 वर्ष पूरे होने को



राष्ट्र प्रथम, संविधान प्रथम

(एक नजर में यात्रा)

2 वर्ष 11 माह 18 दिन
संविधान सभा के परिश्रम का समय

60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन कर 2,000 से अधिक संशोधनों के बाद संविधान को अंतिम रूप मिला

26 नवंबर 1949
संविधान अंगीकृत (स्वीकृत) हुआ

26 जनवरी 1950
संविधान लागू हुआ, भारत गणराज्य बना

19 नवंबर 2015
26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी

2024
संविधान अंगीकार होने के 75 वर्ष, 10वां संविधान दिवस मनाया गया

25 जून 2025
आपातकाल के 50 वर्ष, 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में स्मरण किया

26 नवंबर 2025
76वां संविधान दिवस, संविधान@75 अभियान का समापन, संविधान के प्रति 9 और भाषाओं में जारी

26 नवंबर 2026
12वां संविधान दिवस, संविधान अंगीकार होने के 77 वर्ष

विशेष अवसर बना दिया था। हाथी पर संविधान को सुशोभित कर उसकी शोभायात्रा निकाली थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी स्वयं आगे-आगे पैदल चले थे।

26 नवंबर के बिना 26 जनवरी का महत्व अधूरा है। 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में ही निहित है। यही सोच लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस को जन-उत्सव का रूप दिया। अब प्रत्येक वर्ष केंद्र से लेकर जिला स्तर तक भाषण प्रतियोगिताएं, कर्तव्यों पर व्याख्यान, प्रस्तावना का सामूहिक वाचन, फिल्म-प्रदर्शन और स्कूलों में 'अपने संविधान को जानें' जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 26 नवंबर 2025 को 76वें संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तथा दोनों सदनों के सांसद शामिल हुए। इस अवसर पर विधायी विभाग



द्वारा तैयार भारत के संविधान को नौ और भाषाओं- मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओड़िया और असमिया में जारी किया गया। 'भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी' शीर्षक से एक स्मारक पुस्तिका का लोकार्पण भी हुआ। इसी दिन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन ने 'जीवंत संविधानः लोकतंत्र, गरिमा और विकास के 75 वर्ष' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर वर्ष भर चले 'संविधान@75' अभियान का समापन किया। लेकिन संविधान दिवस के महत्व को समझने के लिए लोकतांत्रिक इतिहास के उस स्याह पन्ने को भी देखना होगा, जब नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए थे। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। विरोध के स्वर को जेलों में बंद कर दिया गया था।

> *हम, अपने लोकतांत्रिक आदर्शों और संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए, हम 25 जून को कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर emergency थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया कि आज भी, मन सिहर उठता है।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

संविधान और आपातकाल की काली रात

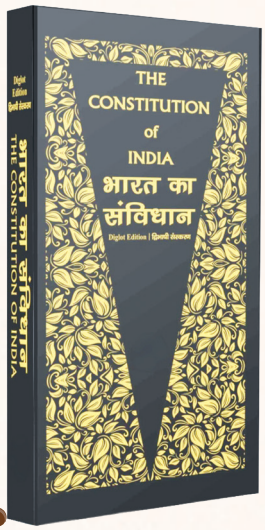
आज देश गर्व से संविधान दिवस मना रहा है और यह एक राष्ट्रीय उत्सव का रूप ले चुका है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकतांत्रिक इतिहास में स्याह पन्ना जोड़ दिया गया था। 'आंतरिक अशांति' के नाम पर देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया गया। यह एकमात्र ऐसा उदाहरण बना जो कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही लागू कर दिया गया था। असल में सरकार कोई भी निर्णय नियमों के आधार पर लेती है, लेकिन यह एक ऐसा उदाहरण है जहां मंत्रियों तक को कुछ पता नहीं था। ऐसे में तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस विषय को कैबिनेट के सामने लाने के लिए कहा और 26 जून को सुबह छह बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। 26 जून को प्रेस पर सेंसरशिप का एक और आदेश जारी हुआ। उस दौर के बारे में प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन ए. सूर्यप्रकाश लिखते हैं, "शायद ऐसा विरला ही उदाहरण होगा, यहां तक कि आपातकाल की खबर न छपे इसके लिए 25 जून की रात ही दिल्ली में बहादुरशाह जफर मार्ग पर प्रेस दफ्तरों की बिजली तक काट दी गई। तानाशाही रवैये और अजीबो-गरीब फैसलों का एक उदाहरण बेंगलुरु का भी है। उस वक्त मैं बेंगलुरु के इंडियन

संविधान दिवस...

26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वर्ष 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था।

भारत के संविधान से जुड़ी कुछ रोचक बातें

- भारत की जनता की पहली प्रतिनिधि संस्था, संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपना महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया।
- संविधान बनाने की प्रक्रिया के दौरान करीब तीन वर्षों तक 53,000 से अधिक नागरिकों ने संविधान सभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बहस-चर्चा देखी और सुनी।
- संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे।
- संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर 1,100 घंटे और 32 मिनट की चर्चा हुई।
- सात सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग समिति ने उसे अंतिम आकार दिया।
- भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं।



- भारत का संविधान टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। इसे अंग्रेजी और हिंदी में हाथ से लिखा गया था। इसमें करीब 90,000 शब्द थे।
- संविधान को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में हाथ से सजाया था। इसकी लिखावट का काम दिल्ली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था।
- संविधान की मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस से भरे विशेष पात्रों में सुरक्षित रखा गया है।
- संविधान के प्रत्येक भाग की शुरुआत भारत के इतिहास के किसी चरण या दृश्य के चित्रण से होती है। इन चित्रों को नंदलाल बोस ने बनाया था। संविधान में कुल 22 चित्र और कलाकृतियां हैं।



- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने नई दिल्ली स्थित संविधान सभा भवन में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया।
- संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। इनमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी और जी. दुर्गाबाई शामिल थीं।
- भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के गणराज्य बनने के बाद जी. वी. मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने।



एक्सप्रेस में ही काम करता था। प्री-सेंसरशिप लागू की जा चुकी थी। इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, बेंगलुरु के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को। यानी एक वर्दी वाले अधिकारी को एक तरह से हमारा संपादक बना दिया गया। वो तय करते थे, क्या छपेगा, क्या नहीं। कौन से शब्दों या फोटो को रखना है या हटाना है। प्रेस काउंसिल एक्ट भी रद्द कर दिया गया था। बहुत से पत्रकार जेल भेज दिए गए।"

वे उस दौर को याद करते हुए आगे यह भी लिखते हैं, "मुझे एक और किस्सा याद है, जब तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री के कहने पर डीएवीपी और ऑल इंडिया रेडियो में सुबह-सुबह फोन किया गया और जो भी अनुवादक थे, उन्हें शास्त्री भवन बुलाया गया। करीब 10-15 अनुवादक, जिन्हें कुछ भी पता नहीं था। उन सभी को विश्व युवक केंद्र ले जाया गया और दोपहर दो बजे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजी में छपा कांग्रेस का घोषणा पत्र दिया गया, जिसका 15 भाषाओं में अनुवाद करना था। रात 10-12 बजे काम खत्म करने के बाद ही वे लोग घर जा सके।" आपातकाल के बारे में लोकसभा में एक परिचर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था, "25 जून की वो रात, देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है, इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेलखाना बना दिया गया था- और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसीलिए। न्यायपालिका का निर्णय था, लेकिन न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वो जीता-जागता उदाहरण है।"

... फिर संविधान संशोधन से असंभव हुआ आपातकाल लगाना

आपातकाल में संविधान के कई प्रावधानों को बदल दिया गया था। जिसे बाद में मोरारजी देसाई की सरकार के समय ठीक किया गया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपातकाल के दौरान जो 42वां संशोधन लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करने और दूसरे ऐसे प्रावधान थे, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते थे - उनको 44वें संशोधन के जरिए बहाल किया गया। इसी संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान के अनुछेद 20 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का आपातकाल के दौरान भी हनन नहीं किया जा सकता

आपातकाल पर लिखी पुस्तक Torture of Political Prisoners in India में वर्णन किया गया है कि कैसे, उस समय की सरकार, लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। मैं चाहूंगा कि देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

है। देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। साथ ही यह भी तय किया गया कि आपातकाल की अवधि को एक बार में छः महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से मोरारजी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि 1975 की तरह देश में आपातकाल को कभी दोहराया न जा सके। यानी जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आपातकाल के दौरान संविधान

संविधान और आपातकाल



आपातकाल...

25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के खतरे का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा की। 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे लंबी रात थी क्योंकि उसकी सुबह 21 महीने के बाद हुई। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा।

- यह भारत के इतिहास का तीसरा आपातकाल था, लेकिन शांतिकाल में लगाया गया पहला था।
- इससे पूर्व 1962 में चीन और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान आपातकाल लगाया गया था।
- उस समय अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित करने का प्रावधान था।
- 1 लाख 10 हजार विपक्षी राजनीतिक नेताओं को जेल में डाला गया।
- 26 जून 1975 से सभी समाचार-पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई।
- संपादकों के लिए समाचार, संपादकीय और तस्वीरें प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी जरूरी थी।



- सेंसरशिप लागू करने के शुरुआती दिनों में दिल्ली के समाचार-पत्र कार्यालयों की बिजली काट दी गई।
- कार्यकर्ताओं, स्वतंत्र संपादकों, पत्रकारों, असंतुष्ट छात्र नेताओं और कई प्रकार के रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों को भी जेल में डाल दिया गया।
- **सामग्री पर नियंत्रण:** संसदीय और न्यायिक कार्यवाही पर सेंसरशिप लगाई गई। अदालतों के फैसलों के प्रकाशित रूप में बदलाव या नियंत्रण किया गया।
- **मीडिया का वर्गीकरण:** समाचार-पत्रों को उनकी संपादकीय स्थिति और कवरेज के आधार पर 'अनुकूल', 'तटस्थ' या 'शत्रुतापूर्ण' श्रेणियों में रखा गया।
- संविधान का ऐसा दुरुपयोग हुआ जो दुःस्वप्न की तरह भारत के लोकतंत्र को हमेशा याद रहेगा।



में की गई गड़बड़ियों को फिर से ठीक किया। न्यायपालिका, संसद और प्रेस के साथ नागरिकों के अधिकारों को फिर से बहाल किया गया। इसलिए मोरारजी देसाई का विशेष स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अवसरों पर कह चुके हैं, "इस तरह से मोरारजी भाई ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकाल लागू कर, 1975 में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की गई थी, वह भविष्य में फिर दोहराया न जा सके। भारतीय लोकतंत्र के महात्म्य को बनाए रखने में उनके अमूल्य योगदान को, आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। एक बार फिर ऐसे महान नेता को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।"

जनता के संवैधानिक अधिकार, सरकार की प्रतिबद्धता

देश की नई पीढ़ी को आपातकाल की घटनाओं से अवगत होना चाहिए क्योंकि भारत के लोगों की ये ताकत है कि उन्होंने

आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए संशोधन

आपातकाल के दौरान संविधान में इतने संशोधन किये गए कि इसे संविधान का 'मिनी वर्जन' कहा गया। प्रस्तावना बदल दी गई, आर्टिकल 14 बदल दिया गया, 7 शेड्यूल बदल दिए गए। 40 अलग-अलग क्लॉज में बदलाव किए गए। नए अनुच्छेद शामिल किए गए, नए खंड डाले गए।

- **38वां संशोधनः** राष्ट्रपति के आपातकाल घोषित करने के फैसले को अदालत में चुनौती देने पर रोक लगाई गई।
- **39वां संशोधनः** प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से बाहर किया गया।
- **42वां संशोधनः** केंद्र की शक्तियां और बढ़ीं। नीति-निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। इसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया।
- **42वां संशोधनः** संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाई गई।
- संविधान संशोधन के 69वें खंड ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी छीनने का काम किया।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया।





लोकसभा चुनाव के बाद आपातकाल का अंत

- लोकसभा चुनाव 16 मार्च से 20 मार्च के बीच हुए और 21 मार्च, 1977 को आपातकाल खत्म किया गया।
- 44वां संविधान संशोधन 1978 में लागू हुआ। इसके जरिए आपातकाल लगाने के आधार के रूप में 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' किया गया।
- न्यायिक समीक्षा बहाल की गई। भविष्य में आपातकाल की घोषणा के लिए कानूनी सुरक्षा के उपाय जोड़े गए।
- 44वां संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का आपातकाल के दौरान भी हनन नहीं किया जा सकता है।
- देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे।
- यह भी तय किया गया कि आपातकाल की अवधि को एक बार में छः महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

लोकतंत्र को जी के दिखाया है। देश की जनता ने मौका मिलते ही लोकतांत्रिक शक्तियों का परिचय दिया था। ये बातें किसी देश के लिए बहुत बड़ी शक्ति का रूप है। लोगों की शक्ति का अहसास करते रहना चाहिए। लोकतंत्र के प्रेमियों ने कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और जन-जन की रग-रग में लोकतंत्र किस तरह व्याप्त है, चुनाव के माध्यम से उस ताकत का प्रदर्शन कर दिया। ये भारत की अमर विरासत है। आपातकाल की बरसी हमें इसी विरासत को और सशक्त करने का स्मरण कराती है। बीते 12 वर्ष में संविधान दिवस के माध्यम से देश में एक नई जागरूकता का संचार हुआ है। आज केंद्र सरकार जनता के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित कर रही है। आज के वक्त में तब की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज अखबारों में आलेख लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर जो चाहे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सरकार के खिलाफ बात कर सकते हैं। आखिर इतनी ऊर्जा कहां से मिली? दरअसल,

नई पीढ़ी के कानून

न्याय अब तेज, सरल और भारतीय

- भारतीय न्याय संहिता (**IPC** के स्थान पर) 511 के स्थान पर अब 358 धाराएं, 20 नए अपराध जोड़े गए, 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (**CrPC** के स्थान पर) 484 के स्थान पर अब 531 धाराएं, 9 नई धाराएं जोड़ी गईं।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (**Evidence Act** के स्थान पर) 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं।
- राजद्रोह की जगह देशद्रोह का प्रावधान- शासन की आलोचना अब अपराध नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी को सशक्त बनाया गया।

कुल **3,200**

सुझावों और गृहमंत्री अमित शाह की 158 बैठकों के बाद तैयार हुए ये कानून।



कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल पाएगा कि किस तरह हमारे संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया, संसद की आवाज दबा दी गई। अदालतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 42वां संशोधन उनके छल-कपट का एक प्रमुख उदाहरण है। गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और दलितों को खासतौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें उनकी गरिमा का अपमान भी शामिल है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत का वर्तमान नेतृत्व उस आपातकाल को करीब से देख चुका है, उस पीड़ा को महसूस करता है। यह ऊर्जा उस आपातकाल की बंदिशों के बीच विरोध करने वाले इन्हीं स्वरों से निकली है।

यही कारण है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने संविधान के 60 वर्ष पूरे होने पर संविधान गौरव यात्रा निकाली थी, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 नवंबर की तारीख को संविधान दिवस के रूप में पुनर्स्थापित किया।

"वी द पीपल" - एक आह्वान, एक प्रतिज्ञा, एक विश्वास

प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित संविधान दिवस समारोह में एक बार कहा था कि संविधान की प्रस्तावना के आरंभिक तीन शब्द- 'वी द पीपल' केवल शब्द नहीं, बल्कि एक आह्वान, एक प्रतिज्ञा और एक विश्वास हैं। इसी भावना के साथ, 26 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर 1949 में संविधान के ऐतिहासिक रूप से अंगीकार किए जाने और राष्ट्र की प्रगति में इसकी स्थायी भूमिका का स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देते हुए यह रेखांकित किया था कि संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। उन्होंने यह भी याद किया कि वह संविधान दिवस विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और गुरु तेग बहादुर जी

की 350वीं शहादत वर्षगांठ के साथ मेल खा रहा था। यानी एकता, बलिदान, राष्ट्रभक्ति और धर्म-रक्षा की चार महान विरासतों का एक ही कालखंड में संगम।

12वें संविधान दिवस पर यह स्मरण और प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यह वर्ष भी उन्हीं ऐतिहासिक स्मृतियों की अगली कड़ी है, जब राष्ट्र आपातकाल के उन काले दिनों को भी कभी नहीं भूल सकता, जिनके 50 वर्ष 2025 में पूर्ण हुए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि 25 जून 1975 को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, नई पीढ़ी उसे कभी नहीं भूलेगी और देश गौरव के साथ अपने संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा का संकल्प लेगा।

अभिव्यक्ति की आजादी को नई मजबूती

संविधान की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी मूल भावना- अधिकार और कर्तव्य की रक्षा में होती है। संविधान के पहले संशोधन ने ही दुर्भाग्य से अभिव्यक्ति की आजादी में कटौती की थी। अंग्रेजी शासन काल का राजद्रोह कानून दशकों तक स्वतंत्र भारत में भी चलता रहा। वही कानून, जिसके तहत महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर जैसे लोग वर्षों जेल में रहे। केंद्र सरकार ने अब भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से राजद्रोह की जगह देशद्रोह का प्रावधान कर शासन की आलोचना को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जबकि देश के विरुद्ध कृत्यों पर कठोरतम दंड का प्रावधान बरकरार रखा है।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली ने 19वीं सदी की जंजीरों से मुक्त होकर सीधे 21वीं सदी में प्रवेश किया है। इन कानूनों को लेकर गृह मंत्रालय ने 2019 से गहन विचार-विमर्श किया, जिसमें कुल 3,200 सुझाव प्राप्त हुए और केंद्रीय गृहमंत्री ने 158 बैठकें कीं। छोटे व पहली बार किए गए अपराधों में जेल की बजाय सामुदायिक सेवा का प्रावधान, तकनीक के उपयोग से समयबद्ध न्याय की व्यवस्था और देशभर में एक समान न्याय प्रणाली, यह सभी सुधार संविधान की मूल भावना, यानी न्याय तक हर नागरिक की समान पहुंच को साकार करने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं।

जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संविधान



अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी

अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया, जिससे वहां भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ।

EWS आरक्षण (103वां संशोधन)

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके (**EWS**) के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी।



OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा (102वां संशोधन)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (**NCBC**) को पूर्ण संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण मिला। 105वें संशोधन के जरिए राज्यों को अपनी **OBC** सूची खुद बनाने की शक्ति भी बहाल की गई।

सुशासन के स्तंभ

योजनाओं में झलकती संविधान की भावना

जन-धन योजना

- जून 2026 तक **59** करोड़ से अधिक बैंक खाते
- जमा राशि **3** लाख करोड़ रुपये पार
- अब तक लगभग कुल **54** लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित



आयुष्मान भारत

- **47** करोड़+ लाभार्थी नामांकित
- **33,000+** सूचीबद्ध अस्पताल
- **70+** आयु के लिए 93 लाख+ आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी



जल जीवन मिशन

- शुरुआत में मात्र **17%** ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन
- 15 अक्टूबर, 2026 तक **82.56%** (15.98 करोड़ परिवार) कवर
- अब 2028 तक विस्तारित (जल जीवन मिशन- 2.0)



पीएम आवास योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

- शहरी में **1.25+** करोड़ घर स्वीकृत (अगस्त 2026)
- ग्रामीण में **3.91** करोड़ स्वीकृत घरों में से 3.12 करोड़ पूर्ण
- 2029 तक **4.95** करोड़ का लक्ष्य

पीएम किसान सम्मान निधि

- 24वीं किस्त (अक्टूबर 2026) तक कुल **4.65** लाख करोड़ रुपये
- **9.44** करोड़ किसान परिवार लाभान्वित



नारी शक्ति वंदन अधिनियम

- संसद-विधानसभा में महिलाओं को **33%** आरक्षण

जीएसटी सुधार 2025

- दो प्रमुख स्लैब (5% व 18%) में सरलीकरण
- **1.65** करोड़+ पंजीकृत करदाता
- 2025-26 में **22.27** लाख करोड़ रुपये कर संग्रह



समानता का सिद्धांतः अंतिम छोर तक विकास की गारंटी

संविधान के मुख्य शिल्पी डॉ. अंबेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां सबको समान अवसर देकर सामाजिक न्याय स्थापित हो। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने 'वंचितों को वरीयता' के सिद्धांत को अपनाते हुए उन लोगों तक स्वयं पहुंचने का प्रयास किया, जिन्हें दशकों तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला था। इसका परिणाम आंकड़ों में भी दिखता है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बीते दस वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं।

जनकल्याण की यह यात्रा योजनाओं की एक पूरी श्रृंखला में झलकती है। हर योजना के ताजा आंकड़े इस यात्रा की गति-प्रगति को बताते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक लगभग 59 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें जमा राशि 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुकी है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का इस्तेमाल कर डीबीटी के माध्यम से 320 से अधिक स्कीम के तहत कुल लगभग 53.80 लाख करोड़ रुपये 15 अक्टूबर 2026 तक सीधे नागरिकों के खाते में भेजे जा चुके हैं। इससे 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि गलत हाथ में जाने से बची है। बिचौलिये खत्म हुए हैं।

“एक जन प्रतिनिधि जो सेवा को एक पवित्र कर्तव्य मानता है, जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करता है, सुशासन के माध्यम से उनकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करता है और विनम्रता, आत्म-अनुशासन एवं विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ समाज की प्रगति की दिशा में समर्पित रहता है, वही वास्तव में जनता का विश्वास, सम्मान, मान्यता और समृद्धि अर्जित करता है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 47 करोड़ से अधिक लोग नामांकित हैं, देशभर के 33,000 से अधिक अस्पताल (17,685 सरकारी और 15,380 निजी) इस योजना से जुड़े हैं। 70 वर्ष से ऊपर के 93 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को अलग से आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 15 अक्टूबर 2026 तक देश के 19.35 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.98 करोड़ (82.56 प्रतिशत) तक नल से जल पहुंच चुका है, जबकि 2019 में मिशन शुरू होने के समय मुश्किल से 17 प्रतिशत घरों में ही यह सुविधा थी। शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए मार्च 2026 में मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी देकर इसे 2028 तक विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत अगस्त 2026 तक 1.25 करोड़ घर स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि ग्रामीण योजना के पहले दो चरणों में स्वीकृत 3.91 करोड़ घरों में से 3.12 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 2029 तक 4.95 करोड़ घरों के लक्ष्य की ओर तेजी से काम जारी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी होने के साथ ही इस योजना के तहत अब तक कुल 4.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि 9.44 करोड़ किसान परिवारों (जिनमें 2.18 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं) तक सीधे पहुंच चुकी है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होकर देश की मातृशक्ति को सम्मानित करने

उपेक्षित इतिहास की पुनर्स्थापना



सेंगोल
नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में प्रतिष्ठित, सत्ता-हस्तांतरण व कर्तव्य-पथ का प्राचीन प्रतीक।

- **संविधान हत्या दिवस (25 जून):** आपातकाल के दुरुपयोग की याद में।
- **विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (14 अगस्त)** विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि।
- **आर्थिक रूप से गरीबों को आरक्षण:** संविधान के 103वें संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण।

श्रीराम मंदिर: 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा।



पद्म पुरस्कार: “जन-पद्म” के रूप में आम नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मान।



12वां संविधान दिवस विशेष

आवरण कथा

एक राष्ट्र, एक चुनाव

- 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति गठित।
- 1951-1967 के बीच देश में एक साथ चुनाव होते रहे थे।
- समिति की रिपोर्ट 2024 में जारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 व यूटी कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी।
- **वर्तमान स्थिति:** दोनों विधेयक सांसद पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली 41-सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास विचाराधीन; रिपोर्ट शीतकालीन सत्र 2026 तक अपेक्षित।
- जेपीसी के अनुमान के अनुसार संभावित बचत 7 लाख करोड़ रुपये और जीडीपी में 1.6% तक की वृद्धि।
- सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची का प्रस्ताव।

प्रस्तावित मॉडल: पहले चरण में लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ, दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव।



> *हम संविधान में निहित सिद्धांतों को मजबूत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं और गरीबों एवं वंचितों के सपनों को पूरा करें।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बन चुका है।

आर्थिक लोकतंत्र: हर नागरिक तक पहुंचा संविधान का न्याय-सिद्धांत

संविधान का समता का सिद्धांत केवल सामाजिक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि यह आर्थिक जीवन में भी उतरा है। सितंबर 2025 में लागू हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने कर ढांचे को केवल दो प्रमुख स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के रूप में सरल बना दिया। साबुन, टूथपेस्ट और ब्रेड जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दिया गया, जीवन-रक्षक दवाओं पर कर घटाकर शून्य या 5 प्रतिशत किया गया। कृषि उपकरणों- ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर पर भी दरें 5 प्रतिशत कर दी गईं जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के लिए वरदान बताया। हस्तशिल्प पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया, जिससे मूर्तियां, पेंटिंग, जड़ाऊ कार्य और हैंडबैग बनाने वाले कारीगरों को बड़ी राहत मिली। खिलौनों और खेल के सामान पर भी दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत की गई, जिससे बाल-विकास से जुड़े एमएसएमई विनिर्माण को बल मिला। इन सुधारों का प्रत्यक्ष लाभ देश के 1.65 करोड़ से अधिक जीएसटी-पंजीकृत करदाताओं तक पहुंचा है, जबकि 2017 में यह संख्या केवल 66.5 लाख थी। कर संग्रह भी लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। वर्ष 2021-22 के करीब 13.76 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में यह लगभग 22.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह गति 2026-27 में भी बरकरार है, अप्रैल-मई 2026 में ही जीएसटी संग्रह लगभग 4.37 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह बताता है कि

किस तरह अधिकांश व्यवसाय औपचारिक कर-व्यवस्था से जुड़ रहे हैं और सरल कर-ढांचा राजस्व वृद्धि में भी सहायक बन रहा है।

आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की यही भावना 'वोकल फॉर लोकल' के रूप में एक जन-आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने पहले 'मन की बात' कार्यक्रम से ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का जो आह्वान किया था, वह आज खिलौना उद्योग जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट परिणाम दे रहा है। जहां भारत ने 2025-26 में प्रमुख खिलौना श्रेणियों में 152 मिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस हासिल किया है, जो वर्ष 2017-18 में व्यापार घाटे की स्थिति से एक बड़ा बदलाव है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत हर जिले की विशिष्ट पहचान को बाजार तक पहुंचाने के प्रयासों से जुड़ी परियोजनाओं का मूल्य 1.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। मार्जिन मनी स्कीम के तहत 6,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, जबकि सवा करोड़ से अधिक ओडीओपी कारीगरों को प्रशिक्षित कर उन्हें आधुनिक टूलकिट भी उपलब्ध कराई गई है। हस्तशिल्प क्षेत्र में राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत 837 करोड़ रुपये की स्वीकृत निधि से 2,325 परियोजनाएं और कार्यक्रम स्वीकृत हुए, जिनसे 66,000 से अधिक कारीगरों को सीधा लाभ मिला। हथकरघा क्षेत्र देशभर में 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इसमें 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल हैं। यह, संविधान की उस भावना का जीवंत उदाहरण है, जिसमें हर हाथ को सम्मानजनक काम और हर कारीगर को उसकी कला का उचित मूल्य मिले।

रक्षा उत्पादन में भी स्वदेशीकरण की यही कहानी दोहराई गई है। रक्षा निर्यात 2013-14 के 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी 56 गुना की वृद्धि। पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के जरिए 5,500 से अधिक रक्षा वस्तुओं की पहचान की गई, जिनमें से 3,000 से अधिक का स्वदेशीकरण फरवरी 2025 तक हो चुका था और एलसीए तेजस, अर्जुन टैंक, आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, कोरवेट, सोनार सिस्टम, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और स्वदेशी रडार जैसी प्रणालियां आज भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी हैं। उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत मार्च 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हो चुका है। 15.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात को सक्षम बनाया है।

संविधान दिवस (2025-26) के विशेष संयोग



■ संविधान अंगीकार होने के 75-77 वर्ष (2024-2026)

इतना ही नहीं 14 लाख से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। यह दर्शाता है कि संविधान द्वारा परिकल्पित समान आर्थिक अवसर अब नीति और क्रियान्वयन दोनों स्तर पर साकार हो रहे हैं।



हमारा संविधान मानव की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। यह हमें अधिकारों से सशक्त तो करता ही है, साथ ही नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें सदैव निभाने का प्रयास करना चाहिए। ये कर्तव्य एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं। आइए, हम अपने कार्यों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

लोकतंत्र की जननी: विश्व मंच पर भारत की प्राचीन विरासत

भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। भारत के पांच हजार वर्ष पुराने वेदों में सभाओं और समितियों की चर्चा मिलती है, महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख है और डॉ. अंबेडकर ने स्वयं बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से करते हुए उसमें प्रस्ताव, कोरम और मतदान जैसे नियमों का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार यह रेखांकित किया है कि लोकतंत्र भारत के लिए केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक संस्कार, एक विचार और एक परंपरा है।

आज जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है और उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत हो रही है, तब पूरा विश्व उसे आशा भरी नजरों से देख रहा है। एक ऐसा देश, जिसकी स्थिरता को लेकर कभी आशंकाएं जताई जाती थीं, आज अपनी विविधता पर गर्व करते हुए पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। नए संसद भवन में स्थापित पवित्र सेंगोल इसी सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। महान चोल साम्राज्य में सत्ता-हस्तांतरण और कर्तव्य-पथ का प्रतीक रहा सेंगोल आज हर सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले संसद भवन में स्थापित होकर भारत की उस संवैधानिक शक्ति की याद दिलाता है, जिसे औपनिवेशिक काल से बाहर निकलते समय अपनाया गया था।

चुनावी सुधार: एक राष्ट्र, एक चुनाव की दिशा में

बार-बार होने वाले चुनावों से विकास की गति में आने वाले ठहराव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति ने व्यापक हितधारक-परामर्श के बाद 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को संसद में पेश करने को मंजूरी दी। दोनों विधेयक फिलहाल सांसद पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली 41 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचाराधीन हैं, जिसने देशभर के हितधारकों से व्यापक परामर्श किया है। समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र 2026 तक का समय दिया गया है। समिति के अनुमान के अनुसार, एक साथ चुनाव कराने से समय के साथ लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और भारत की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। प्रस्तावित व्यवस्था में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने और दूसरे चरण में सौ दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में लगने वाले समय, संसाधन और प्रशासनिक बोझ में भारी कमी आने की उम्मीद है।

अधिकार और कर्तव्य का अटूट रिश्ता

महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी अधिकार, नागरिकों द्वारा सच्ची निष्ठा से निभाए गए कर्तव्यों से ही आते हैं। पिछली शताब्दी के आरंभिक दशकों में जब पूरी दुनिया केवल अधिकारों की बात कर रही थी, गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़कर नागरिकों के कर्तव्यों पर बल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार इस विचार को आगे बढ़ाया है कि संविधान



में जितना महत्व अधिकारों का है, उतना ही महत्व कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा का भी है। संविधान दिवस के अवसर पर होने वाले सामूहिक प्रस्तावना-वाचन का उद्देश्य भी यही है कि हर नागरिक, विशेषकर नई पीढ़ी, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए नागरिक कर्तव्यों को प्राथमिकता दे।

यह भावना केवल भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि नीति निर्माण में भी झलकती है। आईजीओटी (i-got) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी कर्मचारियों को दक्षता और जवाबदेही की नई संस्कृति से जोड़ा गया है तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण ने नागरिक कर्तव्य को स्वच्छता के व्यावहारिक संकल्प में बदल दिया। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के जरिए विभिन्न राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं की आपसी समझ बढ़ाकर भारत की एकता व अखंडता को और सुदृढ़ किया जा रहा है, जो संविधान की प्रस्तावना में निहित 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' के आदर्श का ही विस्तार है।

संविधानवाद की प्राण-प्रतिष्ठा: नई पीढ़ी का संकल्प

बीते 12 वर्षों में भारत और उसके संविधान का मजबूत पक्ष दुनिया ने देखा है। पहले लोकतंत्र संबंधी वैश्विक विमर्श में प्रायः एथेंस, अमेरिका, फ्रांस और मैग्नाकार्टा का ही उल्लेख होता था, प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं प्रायः अनदेखी रह जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की उसी महान लोकतांत्रिक विरासत की प्राण-प्रतिष्ठा की है। संविधानवाद को इस तरह पुनर्स्थापित किया है कि अब कोई भी शासक संविधान के साथ छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं कर सकता। संविधान हत्या दिवस के रूप में हर वर्ष 25 जून को स्मरण करना इसी संकल्प का प्रतीक है कि आपातकाल जैसी घटना का दोहराव देश फिर कभी स्वीकार नहीं करेगा।

निश्चित रूप से 12वां संविधान दिवस केवल एक तारीख का उत्सव नहीं, बल्कि उस सामूहिक चेतना का उत्सव है, जिसमें हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही निष्ठा से निभाता है। जब संविधान सभा के सदस्यों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम से यह महान दस्तावेज हमें सौंपा था, तब उनका सपना था कि आने वाली हर पीढ़ी इसे जिए, इसे समझे और इससे सीखे। आज जब देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो 140 करोड़ नागरिकों की भी यही जिम्मेदारी है कि वे सामूहिक संकल्प के साथ संविधान की प्राण-प्रतिष्ठा के सारथी बनें, जो सच्चे अर्थों में संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य है। ■



दिल्ली में विजयादशमी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पूरी होगी 'राम से राष्ट्र' और 'देव से देश' की परिकल्पना

विजयादशमी के पावन अवसर पर रामलीलाओं में देश की एकता, सामाजिक समरसता और भगवान श्रीराम के आदर्शों का संदेश सुनने को मिला। इस मौके पर 20 अक्टूबर को दिल्ली के एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की बधाई दी। उन्होंने भरोसा जताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय लिया गया 'राम से राष्ट्र' और 'देव से देश' का संकल्प हम सब मिलकर जरूर करेंगे पूरा...

हजारों वर्षों से पूर्वजों ने प्रभु श्रीराम की उपासना की है। यह आस्था केवल इसलिए नहीं है कि श्रीराम ने राक्षसराज रावण का अंत किया था बल्कि इसलिए भी है, क्योंकि प्रभु राम ने ऐसे आदर्श दिये जो मानवता के इतिहास में अतुलनीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभु श्रीराम ने अपने जीवन में कितनी ही कठिनाइयों का सामना किया लेकिन उन्होंने सच्चाई और नीति का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। उनका चरित्र ही ऐसा है कि उनके चेहरे पर न राजपद पाने की प्रसन्नता हुई और न वन जाने से उन्हें कोई दुख हुआ। उन्होंने हर संकट को सहकर भी धर्म का पालन किया और सत्य की स्थापना की।

सामर्थ्य पहचानना और संसाधनों पर करना है विश्वास

प्रभु श्रीराम के जीवन से बड़ी सीख मिलती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। अपना सामर्थ्य पहचानना है, अपने संसाधनों पर विश्वास करना है, अपने संकल्प को शक्ति बनाना है और अपने





देशभर में रामलीलाओं का मंचन, प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जीवंत रखने की परंपरा, अत्याचार और आतंक के अंत का उद्घोष, असत्य पर सत्य सनातन की विजय का विश्वास, यह केवल त्योहार नहीं है, यह भारत की प्राण ऊर्जा है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सफलता का मूल मंत्र

- अपनी शक्ति पर विश्वास।
- अपने सामर्थ्य पर भरोसा।
- अपने संसाधनों का सही उपयोग।
- अपने लक्ष्य के प्रति अटूट संकल्प।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

परिश्रम से समाधान निकालना है। प्रभु श्रीराम ने सिखाया है कि रास्ते की कठिनाइयां, यात्रा को रोक नहीं सकतीं। उन्होंने जनता की सामूहिक शक्ति को जगाया, जनभागीदारी को अपना संबल बनाया, उपलब्ध संसाधनों को जोड़ा और असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बनाया। हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है, हमारे सामने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। हमें जनशक्ति से जनकल्याण करते हुए, जनता की हर आकांक्षाओं को पूरा करना है और इसके लिए भी हमें भगवान राम से ही प्रेरणा भी लेनी है।

गरीब, वंचितों की सेवा सर्वोपरि

जब श्रीराम जंगल गए तो वहां उन्होंने निषादराज को गले लगाया, माता शबरी को सम्मान दिया। उन्होंने दया, करुणा, प्रेम और सौहार्द के मानदंड स्थापित किए। जंगल से वापस आकर अयोध्या के राजा बने तो रामराज्य की स्थापना की जो आज भी सुशासन का मानदंड माना जाता है। रामराज्य अर्थात् ऐसा शासन, जहां किसी के प्रति भेदभाव नहीं हो, जहां सबको न्याय मिले, जहां सबको समान अवसर मिले। पीएम मोदी ने कहा कि जनता को जनार्दन मानकर, नागरिक देवो भव के मंत्र पर आगे बढ़ना है।

विजय का पर्व है विजयादशमी

विजयादशमी, विजय का पर्व है। ये पर्व साहस देता है कि शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न हो लेकिन जब सच्चाई और मानवता साथ होते हैं तो अंत में जीत होती है। विजयादशमी की यही भावना हमेशा से भारत की विचारधारा रही है।

सबको आना होगा एक साथ

देश के दुश्मनों के खिलाफ साथ मिलकर लड़ना होगा। देश के मान-सम्मान को चोट पहुंचाने वाली ताकतें, समाज को बांटने वाले लोग, संस्कृति से नफरत करने वालों की मानसिकता, ये देश के दुश्मन हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अपना संकल्प फिर दोहराना है, मां भारती के शत्रुओं को पहचानना होगा, उन्हें परास्त करना होगा। राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेते हुए, सबको एक साथ आना होगा। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज और कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना को मंजूरी

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी है। यह योजना ग्रामीण शासन व्यवस्था को नेक्स्ट-जेनरेशन गवर्नेंस की ओर ले जाएगी। साथ ही, कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना, खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत के प्रस्तावों को दी गई मंजूरी...

निर्णय : वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी।

प्रभाव : केंद्र प्रायोजित यह योजना विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा देने की पहल है।

- इस योजना से 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
- यह योजना पंचायतों की क्षमता को सुदृढ़ करेगी, ताकि वे वित्त आयोग के अनुदान और अन्य निधियों का प्रभावी उपयोग कर सकें एवं स्वयं के स्रोतों से राजस्व (ओएसआर) जुटा सकें। ऑनलाइन लेखांकन, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण सुनिश्चित कर सकें।
- योजना से संसाधनों के पारदर्शी उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय विकास संबंधी कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी और जवाबदेह एवं आत्मनिर्भर पंचायतों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय पहलों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंच बनाई जाएगी।
- इस योजना का कुल परिव्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है।





हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी है। इससे स्थानीय संसाधनों, क्षमताओं और चुनौतियों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। इस कदम से जनभागीदारी को और बल मिलेगा, जिससे सतत विकास के लक्ष्यों को तेजी से हासिल किया जा सकेगा। ***– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री***

निर्णय : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी।

प्रभाव : यह 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

- इसमें मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 60 प्रतिशत की दर के अतिरिक्त 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, ताकि बढ़ती महंगाई की भरपाई की जा सके।
- महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
- यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है।

निर्णय : विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल विनिर्माण परितंत्र विकसित करने के लिए खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी।

प्रभाव : इस योजना का उद्देश्य निवेश, विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना तथा खेल उपकरण क्षेत्र में दुनिया भर में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

- इसका लक्ष्य निवेश, प्रौद्योगिकी अंगीकार, अनुसंधान एवं नवाचार, कौशल विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और बाजार विकास के लिए लक्षित सहायता के माध्यम से भारत के खेल उपकरण विनिर्माण आधार को मजबूत करना है।
- यह योजना विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल उपकरण उद्योग के विकास को मदद करेगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।
- वर्ष 2026 से 2033-34 की अवधि के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

निर्णय : वित्त वर्ष 2039-40 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना' (सीएमपीएस) को मंजूरी।

प्रभाव : इस योजना का उद्देश्य भारत में विश्व-स्तरीय प्रतिस्पर्धी कंटेनर निर्माण का इकोसिस्टम तैयार करना, आयात पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति श्रृंखला को और भी अधिक मजबूत बनाना है।

- इस योजना का मकसद नई निर्माण इकाइयों को समर्थन देना और मौजूदा कंटेनर निर्माण इकाइयों का विस्तार करना है।
- वार्षिक घरेलू कंटेनर निर्माण क्षमता में 7.5 लाख टीईयू तक लगभग 10 गुना की वृद्धि होगी।
- गुणवत्तापूर्ण शिपिंग कंटेनरों के लिए भारत को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता के साथ एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी विनिर्माण आधार तैयार होगा।
- भारत की समुद्री और रसद आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुकूलन को मजबूती मिलेगी।
- अनुमानित 3,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जबकि कॉर्नर कास्टिंग, विशेष स्टील, लकड़ी के फ्रेम और पेंट जैसे सहायक उद्योगों को समर्थन मिलेगा।
- कंटेनर विनिर्माण योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।



पीएम आवास-ग्रामीण के 10 वर्ष



स्थिरता... अवसर... भविष्य के लिए आशा की नींव

आवास का निर्माण किसी भी परिवार के लिए सुरक्षा, खुशी और सम्मान एक साथ लेकर आता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार न सिर्फ आर्थिक सहायता दे रही है बल्कि उसके साथ बिजली, पानी, शौचालय, गैस कनेक्शन भी दे रही है। बीते एक दशक में देश में ग्रामीण आवास की यात्रा बदलाव और गरिमा की कहानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 2029 तक 4.95 करोड़ आवास दिए जाने का है लक्ष्य...

मकान केवल ईंट, सीमेंट से तैयार ढांचा नहीं बल्कि इससे हमारी भावनाएं, हमारी आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। घर की चहारदीवारी हमें सुरक्षा तो प्रदान करती ही है, साथ ही हमारे अंदर एक बेहतर कल का भरोसा और विश्वास भी जगाती है। इसी भाव और भरोसे को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के आगरा से किया था। पीएमएवाई-जी से बीते एक दशक में 3.91 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए जिनमें से 3 अगस्त, 2026 तक 3.12 करोड़ आवासों का निर्माण पूर्ण करके आवंटित भी किए जा चुके हैं। अभी 79 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। आवास सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण हो इसके लिए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4 लाख राजमिस्त्री को प्रशिक्षण भी दिया है। योजना में जो लक्ष्य रखे गए हैं, उनमें से न्यूनतम 60 फीसदी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभार्थियों के लिए आरक्षित है।

महिला सशक्तीकरण

पीएमएवाईयू 2.0 में केंद्रीय सहायता से निर्मित या खरीदे गए आवास परिवार की वयस्क महिला मुखिया के नाम पर अथवा परिवार के पुरुष मुखिया एवं उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होने चाहिए। केवल उन मामलों में जहां परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य उपलब्ध न हो, आवास परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है। जुलाई, 2026 तक पीएमएवाईयू 2.0 में 16.20 लाख मकान स्वीकृत किए गए जिनमें से 12.62 लाख मकान महिलाओं के नाम स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पीएम आवास योजना-शहरी में स्वीकृत 1.27 करोड़ से अधिक आवासों में से 1 करोड़ आवास महिलाओं के लिए नाम स्वीकृत किए गए हैं।

एआई से ग्रामीण आवास की निगरानी

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में यह भी सुनिश्चित कर रही है कि बनाया गया प्रत्येक घर वास्तविक हो और प्रत्येक लाभार्थी सत्यापित हो। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल के नए आयाम को निगरानी के लिए जोड़ा गया है।

- **अनुशंसा प्रणाली** : एआई मॉडल अपलोड की गई तस्वीरों से दीवारों, छतों, दरवाजों और खिड़कियों जैसी घरों की विशेषताओं की पहचान करता है। केवल वास्तविक और पूर्ण घरों को अंतिम रूप से चुनकर उसके पूर्ण हो जाने को सुनिश्चित करता है।
- **धोखाधड़ी की रोकथाम** : मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक ही इलाके में घरों की तस्वीरों के साथ दूसरे घरों की तुलना करते हैं। यदि समानताएं पाई जाती हैं, तो सिस्टम दोहराव या धोखाधड़ी रिपोर्टिंग को रोकने के लिए अलर्ट करता है।
- **चेहरा प्रमाणीकरण और ईकेवाईसी** : लाभार्थियों को आधार के जरिए, एआई-सक्षम चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। आवास+ 2024 मोबाइल ऐप 3डी हाउस डिजाइन जैसी नवीन सुविधाओं के साथ आधार फेस ऑथेंटिकेशन को एकीकृत करके लाभार्थी की पहचान में पारदर्शिता को और बढ़ाता है।



“पीएम आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों लाभार्थियों को अपना पक्का घर मिल चुका है। सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है।

–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पीएम आवास योजना - शहरी

देश के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग आदि श्रेणियों के लिए 1.12 करोड़ आवासों की मांग सामने आई। 25 जून, 2015 से शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 में 111.48 लाख आवास और पीएमएवाईयू 2.0 में 16.20 लाख मकान सहित कुल 127.68 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 121.03 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। 13 जुलाई, 2026 तक देश भर में 99.07 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

राष्ट्र विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सशक्त ग्रामीण आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ऐसे में आने वाले वर्ष व्यापक ग्रामीण आवास प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक चरण के प्रतीक होंगे। चरण I और II में 3.12 करोड़ घरों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। आवास वितरण को गरिमा, सशक्तीकरण और सुविधाओं से जोड़कर, इसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। यह प्रगति सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पात्र परिवार के पास एक स्थायी घर होगा। 2029 के लिए एक स्पष्ट रोडमैप के साथ, यह योजना ग्रामीण भारत में ‘सबके लिए आवास’ की सोच को मूर्त रूप देगी। ■



आरबीआई के डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन

सुशासन से संतुलित विकास

भारत आज, दूरदराज क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब परिवार को सम्मान के साथ जीने के लिए सुविधाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ ही सुरक्षित वित्तीय समावेशन पर काम कर रहा है। ऐसे सेवा और संसाधन विकसित किए जा रहे हैं जिससे नागरिकों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि विकास की यात्रा में वह पीछे नहीं छूटेगा। इन सबके बीच भारत अपनी वित्तीय प्रणाली को भी सुरक्षित बना रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को ओडिशा में भारतीय रिजर्व बैंक के नवनिर्मित डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का किया उद्घाटन...

नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और उनके सपनों को नए अवसर प्रदान करना ही वर्तमान सरकार का वास्तविक उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत में गवर्नेंस की अप्रोच तेजी से बदल रही है। आरबीआई की ये नई सुविधाएं, भारत की एक नई प्राथमिकता को भी दर्शाती हैं। आज सरकार का फोकस - विकास की प्राथमिकता, विकास का विस्तार और विकास की आखिरी व्यक्ति तक पहुंच है। दशकों तक विकास का लाभ देश के हर क्षेत्र, हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचाना एक चुनौती बना रहा है। इसी सोच को बदलने का प्रयास किया है। हम जन-हितैषी, सक्रिय और सुशासन के मॉडल से प्रेरित हैं। विकास का अर्थ भारत की न्यायसंगत प्रगति है, जहां अवसर हमारे गांवों और छोटे शहरों तक एक समान पहुंचें। हमारा लक्ष्य है, दूर-दराज के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देना, गरीब परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने की सुविधाएं देना और हर नागरिक को निरंतर यह विश्वास देना कि विकास की यात्रा में वह पीछे नहीं छूटेगा।

अब बैंकिंग होगी अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित

भारत ने बीते दशक में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

विकसित भारत का सशक्त इंजन पूर्वी भारत

भुवनेश्वर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया कि विकसित भारत के निर्माण में पूर्वी भारत विकास का एक सशक्त इंजन बनेगा। ओडिशा में वर्तमान सरकार के नेतृत्व में विकास कार्यों को नई गति मिली है। राज्य अपने पारंपरिक खनिज-आधारित उद्योगों के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और उन्नत कंप्यूटिंग के नए इकोसिस्टम को विकसित कर रहा है। इस तरह ओडिशा खदानों से लेकर माइक्रोचिप तक की विकास यात्रा के माध्यम से अपने भविष्य के बड़े अवसर बना रहा है। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि विकास के ये उभरते क्षेत्र व्यापक अवसरों के द्वार खोलेंगे।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

मोदी ने कहा है कि आने वाला दशक ओडिशा के नए डेटा सेंटर और मजबूत कंप्यूटिंग प्रणालियों की मदद से बैंकिंग सेवाओं को अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाने के लिए समर्पित है। पीएम मोदी कहते हैं कि आजकल युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते। किसी देश को कमजोर करना है, तो उसकी इकोनॉमी पर अटैक करके भी ये किया जा सकता है। ऐसे में जब भारत, आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, तो हमें अपने बैंकिंग सिस्टम को भी साइबर लुटेरों, साइबर आतंकियों से सुरक्षा देना अनिवार्य है। आज साइबर खतरा और इसका नेचर बदल रहा है। ऐसी नई चुनौतियों का सामना पुरानी व्यवस्थाओं, पुराने ट्रेनिंग सिस्टम, पुराने ट्रेनिंग टूल्स से नहीं कर सकते। इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और कुशल मानव संसाधन भी चाहिए। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी संस्थान का रोल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है।

सरकारी सहायता वितरण में लीकेज समाप्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 तक आधी से अधिक आबादी बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थी। मध्यम वर्ग के लिए बैंक से लोन लेना दूर का सपना था। छोटे किसान, भूमिहीन और महिलाओं के लिए इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। वित्तीय समावेशन के आधुनिक दौर ने देशभर में इस स्थिति को बदल दिया है। आज भारत में डिजिटल बैंकिंग ने हर किसी को 24 घंटे बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिया है। हर परिवार लाभार्थी बन गया है। अब सरकारी

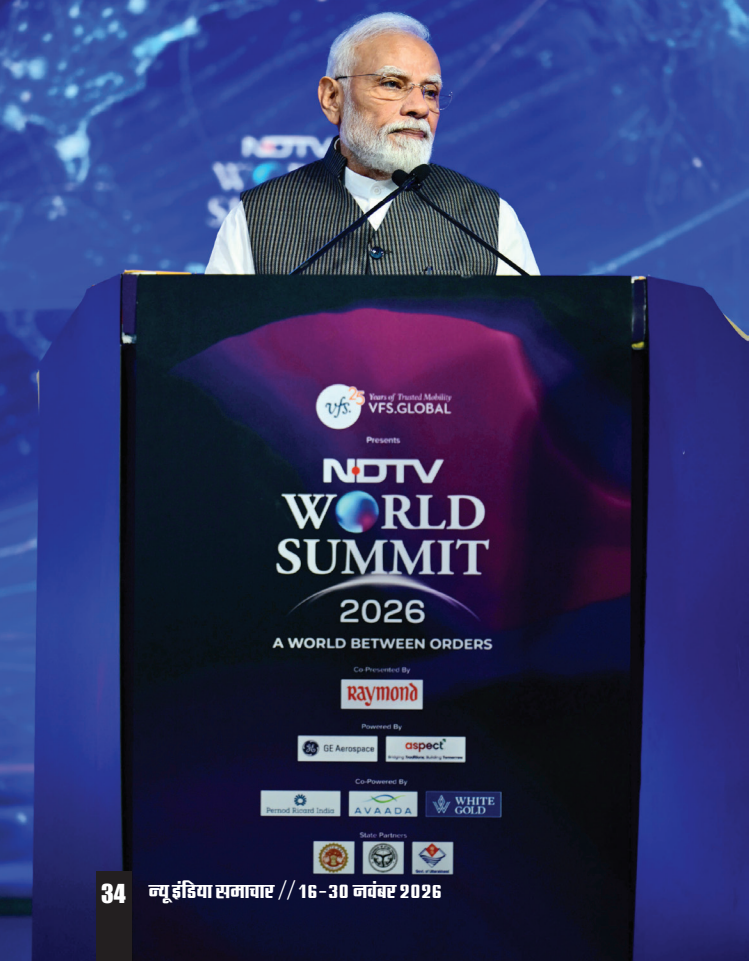


सहायता के वितरण में होने वाली किसी भी तरह की लीकेज पूरी तरह समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार जितना पैसा भेजती है, एक-एक रुपया अब बिना किसी कटौती के सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। यह देश में खोले गए लगभग 60 करोड़ जनधन खातों के कारण ही संभव हो पाया है। ■

भारत के सामर्थ्य से बढ़ेगा विश्व का सामर्थ्य

'विकसित भारत' का संकल्प न केवल 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व की गारंटी भी है। भारत अब केवल दुनिया का 'बैक ऑफिस' नहीं, बल्कि नवाचार और समाधान देने वाला 'ब्रेन ऑफिस' बनकर पूरी मानवता को सशक्त कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्थान और ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज, आज है समय की मांग...

> विकसित भारत सिर्फ हमारे लिए नहीं हैं। ये एक बेहतर विश्व की भी गारंटी है।
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**



एनडीटीवी वर्ल्ड समिट-2026 में 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक बदलाव अब आम नागरिकों के दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। इन बदलावों का वास्तविक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव अंतरराष्ट्रीय मंचों की आवश्यकता को और बढ़ाता है। 'द वर्ल्ड बिटवीन आर्डर्स' (अव्यवस्था और नई व्यवस्था के बीच की दुनिया) विषय को चर्चा के केंद्र में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक समुदाय को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मौजूदा विश्व व्यवस्था में बदलाव क्यों आ रहे हैं और पुरानी व्यवस्थाएं आज के संकटों का समाधान करने में क्यों विफल हो रही हैं।

कभी देशों को जोड़ने वाले व्यापार, प्रौद्योगिकी और समुद्री मार्ग अब हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में आज आवश्यकता ऐसी समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण की है, जो संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया और वर्तमान वास्तविकताओं के बीच की खाई को खत्म कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा, "और यहीं से भारत की भूमिका का सवाल प्रमुखता से सामने आता है।" पीएम मोदी ने कहा कि "यदि सदी बदल जाए और हम न बदलें, तो बदलाव लाने की हमारी क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है।" ऐसे में जरूरी है कि उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में बहुपक्षीय संस्थानों में

कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियों का प्रधानमंत्री ने किया जिक्र...

300 गीगावाट

भारत ने पहली बार गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का आंकड़ा किया पार।



- **25%** की वृद्धि दर्ज की गई सितंबर महीने में वस्तुओं के निर्यात में।
- दोगुने से भी अधिक हो गया समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात पिछले 12 वर्ष में।
- **3.5** करोड़ से अधिक लखपति दीदियां बन चुकी हैं, लक्ष्य 6 करोड़ बनाने का।
- **70** लाख नए रोजगार सृजित किए जा रहे हैं पीएम विकसित भारत रोजगार योजना में।
- **12** लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर का लाभ मध्यम वर्ग को दिया जा रहा।
- शोध प्रकाशनों में भारत तीसरे स्थान पर है।
- **1.5** लाख पेटेंट आवेदन वर्ष 2025 में दाखिल किए गए।
- **20%** हिस्सा भारत में, वैश्विक चिप-डिजाइन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का।
- 2 से 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन करने में सक्रिय रूप से जुटे हैं भारतीय इंजीनियर।
- **325** से अधिक चिप डिजाइन तैयार किए हैं अब तक देश के विद्यार्थियों ने।
- भारत में स्थित हैं दुनिया के आधे से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण देकर बताया कि भविष्य के संकटों से निपटने की तैयारी के लिए बनाई गई सरकारी नीतियों और दीर्घकालिक निवेशों की दूरदर्शिता का नतीजा है कि दवा उद्योग, जो पहले कच्चे माल के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर हो रहा है। इसमें पीएलआई योजना की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाचार को बढ़ावा देने, नए रास्ते तलाशने, चुनौतियों को अवसरों में बदलने और भारत की सफलता को वैश्विक समृद्धि से जोड़ने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "हम बड़े सपने देखेंगे, हर चुनौती को अवसर में बदलेंगे और अपने हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे।"



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

सुधार और ग्लोबल साउथ की आवाज को तत्काल उचित स्थान दिया जाए।

शक्तिशाली देश कमजोर देशों का शोषण न करें। इसी दृष्टिकोण से भारत ने कोविड-19 के दौरान आगे बढ़कर 100 से अधिक देशों को टीके और दवाईयां उपलब्ध कराई। सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए भारत ने जी-20 और ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के दौरान आम सहमति बनाई और दोनों ही अवसरों पर सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणापत्र पारित कराने में सफलता हासिल की। भारत की बढ़ती शक्ति को वैश्विक कल्याण से सीधे जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की नीतियां क्षणिक आवेगों की बजाय शाश्वत सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित हैं। इसलिए, एक सशक्त भारत वैश्विक स्थिरता और निरंतरता की गारंटी देता है।



विकसित भारत का आधार...
वैज्ञानिक अनुसंधान और इनोवेशन

'विकसित भारत' के संकल्प की सिद्धि वैज्ञानिक अनुसंधान, मौलिक खोजों और नवाचार की मजबूत नींव पर टिकी है। भारत को न केवल नई खोजों को अपनाना होगा, बल्कि भविष्य की तकनीकों को दिशा देकर विश्व का नेतृत्व भी करना होगा। इसके साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तीव्र तकनीकों के दौर में नवाचार की गति के साथ-साथ विश्वसनीयता, सटीकता और तथ्यों की प्रामाणिकता बनाए रखना भी अनिवार्य है। इसी पहलू को आगे बढ़ाने वाले विषय 'उभरता विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026' का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को किया उद्घाटन...

भारत के युवा जिस स्तर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह बहुत उत्साहजनक है। पहले भारत विदेशी इनोवेशन को कई वर्षों बाद अपनाकर या उनमें बदलाव कर उनके पीछे-पीछे चलता था। आज का भारत मौलिक तकनीक विकसित कर दुनिया भर की चुनौतियों का समाधान निकालने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने से लेकर चंद्रमा के अनछुए दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने में सफलता पाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य की तकनीकों को अपनाना चाहिए, साहसपूर्वक नवाचार करना चाहिए और इन तकनीकों को बनाने में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए।

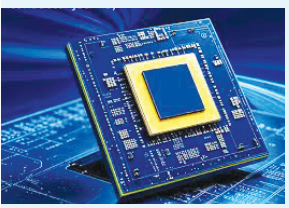
शून्य और संख्या प्रणाली के आविष्कार से लेकर खगोल विज्ञान तक भारत की खोजों की समृद्ध विरासत है। देश आधुनिक तकनीक और नए आत्मविश्वास के साथ इस वैज्ञानिक विरासत को आगे बढ़ा रहा है। पिछले एक वर्ष में हासिल की गई कई उपलब्धियां इसका प्रमाण हैं।

लैब तकनीक

12,000 करोड़ रुपये लैब तकनीकों पर सरकार ने खर्च किए। वहीं निजी निवेशकों द्वारा भी पिछले एक वर्ष 12 **हजार करोड़** रुपये खर्च किए गए। एक वर्ष में ही शोध और विकास के लिए कुल 24 **हजार करोड़** रुपये खर्च किए गए हैं।

एक साल की सफलता...

- **1.5** लाख से अधिक हुई सालाना पेटेंट की संख्या जो 10 वर्ष पहले 50,000 से भी कम थी।
- स्वदेशी **500**-मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक 'फर्स्ट क्रिटीकेलिटी' (पहली बार परमाणु शृंखला अभिक्रिया शुरू करने की स्थिति) हासिल कर ली है।
- भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने 'मेड-इन-इंडिया' रॉकेट का इस्तेमाल कर अपने पहले ही प्रयास में उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। देश ने 'सैटेलाइट डॉकिंग' (अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को आपस में जोड़ने) की क्षमता हासिल की है।
- देश ने 'एआई इम्पैक्ट समिट' की मेजबानी की, अपना एआई मॉडल लॉन्च किया। भारत में बनी सेमीकंडक्टर चिप का दुनिया भर में निर्यात शुरू किया गया।



भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्र

- सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, एआई, सिंथेटिक बायोलॉजी और ऑटोनॉमस सिस्टम।

प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में मौजूद हर शोधकर्ता, उद्योग जगत के नेता, स्टार्टअप संस्थापक और विद्यार्थी से तीन वर्ष का ठोस लक्ष्य तय करने को कहा।

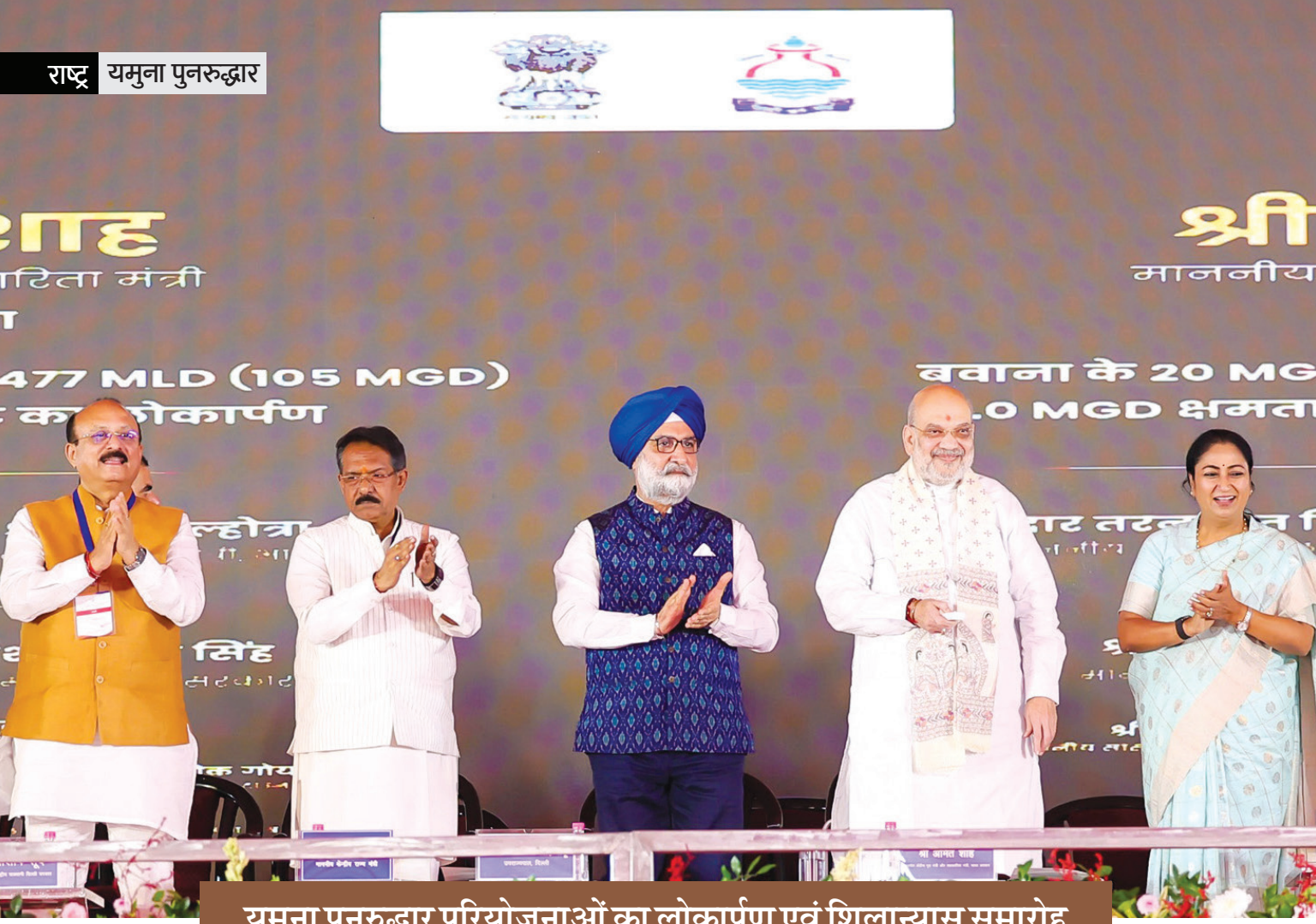


एआई हमें जवाब जल्दी दे सकता है। लेकिन जवाब की सत्यता परखने की जिम्मेदारी वैज्ञानिक की होनी चाहिए।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विज्ञान की असली सफलता प्रयोगशाला से बाहर निकलकर आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, बड़ी समस्याओं को सुलझाने और स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, रोजगार तथा आपदाओं से निपटने की क्षमता को मजबूत करने में है। भारतीय स्टार्टअप इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे स्टार्टअप और घरेलू कंपनियों का उदाहरण दिया जो कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे- मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने के लिए पहनने योग्य ईईजी तकनीक, स्वदेशी वायरलेस और सैटेलाइट संचार, विशेष पोषण उत्पाद, नई सेमीकंडक्टर तकनीक और स्टील स्लैग जैसे औद्योगिक कचरे का उपयोग करने वाले समाधान का सामने आना। ■



यमुना पुनरुद्धार परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह

2029 तक निर्मल बनेगी यमुना

दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ मिल कर केंद्र सरकार ने एक ऐसा रोडमैप तैयार किया है, जिसके माध्यम से 2029 तक यमुना को निर्मल बना दिया जाएगा। इसी कड़ी में 22 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनरुद्धार से जुड़ी 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ऐसी दिल्ली बनाना चाहती है, जहां घर सुंदर हों, पानी शुद्ध हो, गलियां साफ हों, कूड़े के पहाड़ न हों और यमुना निर्मल होकर दिल्ली से संगम तक जनता को अपना आशीर्वाद दे सके। यही कारण है कि यमुना पुनरुद्धार परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम को एक अडिग संकल्प के रूप में लिया है। आज इस संकल्प के एक बड़े भाग की पूर्ति हो रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज यहां 10 परिजनाओं का लोकार्पण हुआ और 33 परिजनाओं



सजती-संवरती दिल्ली

- प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली सरकार के समक्ष यमुना को प्रदूषणमुक्त बनाने की कार्ययोजना रखी। इस योजना का 40% कार्य पूरा हो चुका है।
- पिछले करीब 30 साल से दिल्ली के गटर के पानी को यमुना में छोड़ने और हर रोज डेयरियों का 2,000 टन गोबर यमुना में डाल दिया जाता था।
- कूड़े के पहाड़ों के नाम पर राजनीति होती रही। वर्तमान में दिल्ली सरकार ने कूड़े के पहाड़ों को नीचे लाने का काम किया, 2 साल बाद इन कूड़े के पहाड़ों की जगह बगीचा बन जाएगा।
- दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की सहायता से 2.17 करोड़ मीट्रिक टन कचरा साफ कर 100 एकड़ भूमि को कचरे से मुक्त कराया है।
- ओखला और भलस्वां में कूड़े का पहाड़ 30 से 40 मीटर नीचे आया है। गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ 10 से 15 मीटर नीचे आया है।

> *हमने तीन साल का एक एक्शन प्लान बनाया है जिसमें दिल्ली के हर घर को सीवेज कनेक्शन देंगे, इससे गंदे पानी की निकासी होगी। साथ ही, हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम भी करेंगे।*
>
> **– अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**



की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि 8,941 करोड़ रुपये की कुल लागत से शुरू हुई परिजनाओं के माध्यम से कई लाख लीटर पानी शुद्ध होकर यमुना में जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों से जुड़ी परियोजनाओं का यहां लोकार्पण हुआ और एसटीपी के उन्नयन एवं नए एसटीपी लगाने का शिलान्यास भी हुआ है। विकेंद्रीकृत एसटीपी पंपिंग स्टेशन भी बना है और सीवर लाइनों को घरों से जोड़ने का काम भी शुरू हुआ है। गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मई, 2029 से पहले यमुना जी को शुद्ध कर देंगे।

यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प को नई गति

दिल्ली सरकार की जल उपचार संयंत्र, रीसाइक्लिंग प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज पंपिंग स्टेशन और हाउसहोल्ड सीवर कनेक्शन की इन परियोजनाओं से प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी शोधित होकर यमुना में पहुंचेगा। यह यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प को नई गति देगा। ■

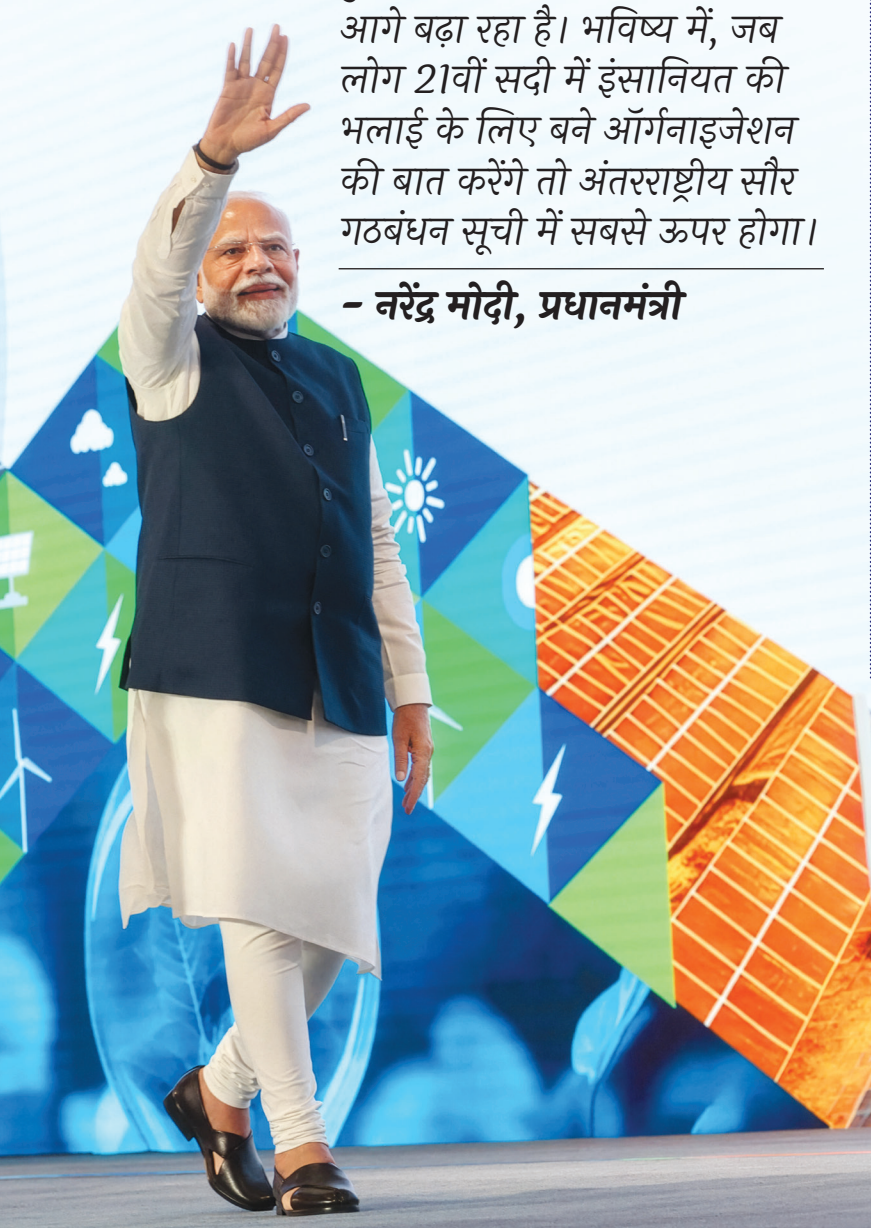
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 11 वर्ष

सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार की किरण

सौर ऊर्जा वास्तव में वर्तमान समय की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक संपदाओं में से एक बनकर उभरी है। सौर ऊर्जा का यह परिवर्तन अंततः ऊर्जा से कहीं अधिक है। यही वजह है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से 30 नवंबर, 2015 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की भारत-फ्रांस ने संयुक्त रूप से शुरुआत की। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में दे रहा है योगदान...



“अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को आगे बढ़ा रहा है। भविष्य में, जब लोग 21वीं सदी में इंसानियत की भलाई के लिए बने ऑर्गनाइजेशन की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सूची में सबसे ऊपर होगा।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत और फ्रांस ने वैश्विक विकास के केंद्र में सूर्य की शक्ति को स्थापित करने के साहसिक विजन के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी-21) के दौरान शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने इस विचार को एक वैश्विक आंदोलन में परिवर्तित करने में मदद की। पिछले 11 वर्षों में, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने सौर ऊर्जा की संभावनाओं को दुनिया भर में वास्तविक, जीवन-परिवर्तनकारी प्रभाव में बदलने में मदद की है। जहां सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संगठन की शुरुआत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, सौर ऊर्जा से समृद्ध देशों के साथ बेहतर तालमेल के जरिए सौर ऊर्जा की मांग को पूरा करने, सौर ऊर्जा को सस्ता करने, भरोसेमंद और व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आज, 130 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए समर्पित सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय सौर

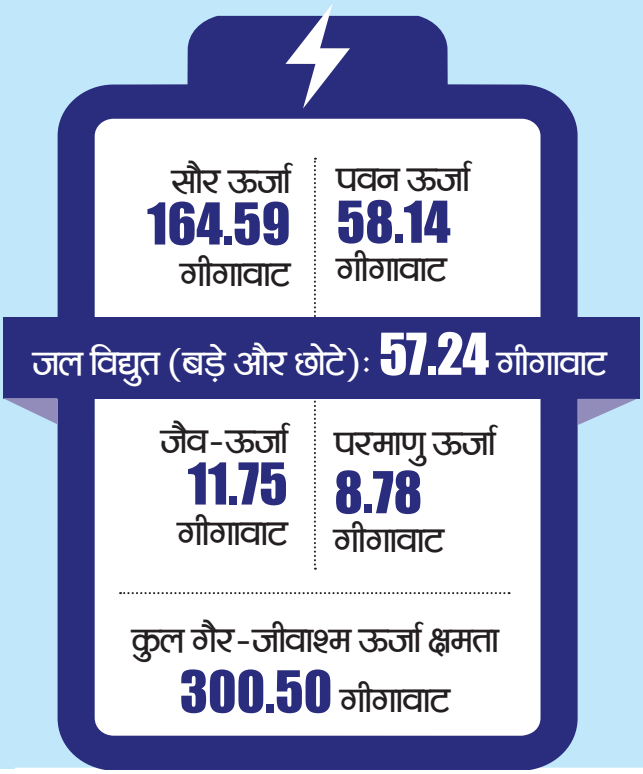
आईएसए के 4 रणनीतिक स्तंभ

- **कैटेलिटिक फाइनेंस हब:** व्यापक स्तर पर निवेश जुटाने और बढ़ावा देने के लिए।
- **वैश्विक क्षमता केंद्र और डिजिटलीकरण** नवाचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए।
- **क्षेत्रीय और देश-स्तरीय सहभागिता** अनुकूलित उपायों को संचालित करने के लिए।
- **प्रौद्योगिकी रोडमैप और नीति:** उभरती सौर प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के लिए।

एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी मंच के रूप में, आईएसए अपने सदस्य देशों को सौर ऊर्जा को व्यापक स्तर पर अपनाने में सहायता करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, नीतिगत नेतृत्व और वैश्विक समन्वय प्रदान करता है।

सूरज, पानी, हवा, परमाणु से बिजली

भारत गैर-जीवाश्म ईंधन यानी सूरज, पानी, हवा और परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। 31 जुलाई, 2026 तक यह उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है, यह उसका 60 प्रतिशत से अधिक है। इतना ही नहीं देश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 552 गीगावाट में गैर-जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली का हिस्सा 54 फीसदी से अधिक हो गया है।



स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट से बढ़कर वर्तमान में लगभग 165 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा क्षमता भी 2014 में 21 गीगावाट से बढ़कर 58 गीगावाट से अधिक हो गई है।

गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। इससे 'एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड' को प्रोत्साहन मिल रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, सौर सिंचाई और ग्लोबल सोलर फैसिलिटी सहित अभिनव वित्त पोषण प्लेटफार्मों जैसी पहलों के माध्यम से, सदस्य देशों को सौर समाधान तैनात करने में मदद कर रहा है। आईएसए के कार्य इस बात के प्रमाण हैं कि ऊर्जा परिवर्तन समावेशी, जन-केंद्रित और परिवर्तनकारी हो सकता है। आईएसए ने हाल ही में, अपने सदस्य देशों और साझेदारों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है।

भारत में सौर ऊर्जा का विकास एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। सौर बाजार में भारत की उपलब्धियां निरंतर नीतिगत समर्थन, बढ़ते विनिर्माण, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती जन भागीदारी को दर्शाती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई आईएसए पहल के साथ ही भारत जैसे-जैसे अपनी पंचामृत प्रतिबद्धताओं और 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें सौर ऊर्जा एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। भारत के गैर-जीवाश्म ईंधन में 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की प्राप्ति में भी सौर ऊर्जा की मजबूत भागीदारी रहेगी। ■

काशी का नमो घाट

वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन

अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 25 अक्टूबर को नमो घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायु सेना दिवस पर हवाई प्रदर्शन-2026 के साक्षी बने। साथ ही, उन्होंने एक नई वस्त्र निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया जिससे लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का एक रोड शो भी हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने किया उनका भव्य स्वागत...

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक नई वस्त्र निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। यह सुविधा भारत के कपड़ा और परिधान निर्माण ईको सिस्टम को मजबूत करने और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक विनिर्माण प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह सुविधा विशेष रूप से महिलाओं के लिए सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में योगदान देगी। उद्घाटन में औद्योगिक निवेश और विनिर्माण के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। यहां बने कपड़े दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचेंगे। मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाली पहल होने के नाते, यह महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह पहल वाराणसी के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और आगे बढ़ने के भी नए अवसर ही देगी।

राफेल-मिराज ने दिखाया शौर्य

प्रधानमंत्री वाराणसी के नमो घाट पर वायु सेना दिवस पर हवाई प्रदर्शन-2026 के गवाह बने। यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम 'विंग्स ओवर गंगेज' रखी गई। इस हवाई प्रदर्शन में तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड, एसयू-30एमकेआई और राफेल सहित परिवहन विमान भी शामिल हुए। इस आयोजन में भारतीय वायु सेना की प्रमुख प्रदर्शन टीमों में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया। प्रदर्शन में



काशी में रोड शो के दौरान अपने परिवारजनों से मिले अपार स्नेह और आशीर्वाद ने भावविभोर कर दिया।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

सटीक उड़ान, समन्वय और परिचालन उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान Su-30 लड़ाकू विमान ने दो जगुआर विमानों को बीच में रोककर भारतीय वायुसेना की युद्धक रणनीति और हवाई रक्षा क्षमता की झलक दिखाई। वहीं, तीन राफेल लड़ाकू विमानों ने 'नीलकंठ फॉर्मेशन' में एक साथ उड़ान भरते हुए शानदार 'थ्री-वे स्प्लिट' का प्रदर्शन किया। इन सटीक हवाई करतबों ने भारतीय वायुसेना के कौशल और आपसी तालमेल को दर्शाया।



PMO India
@PMOIndia

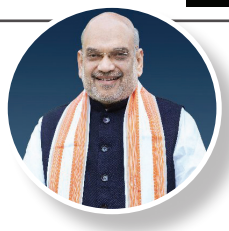
हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, विकसित भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है।

और हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण को, किसानों को सशक्त करने को प्राथमिकता दी है: PM @narendramodi



Rajnath Singh @rajnathsingh ·

सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखंडता को आकार दिया, लेकिन लंबे समय तक उनकी गौरवशाली विरासत को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। प्रधानमंत्री @narendramodi ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दिवस और देशव्यापी आयोजनों के माध्यम से उनकी गौरवशाली विरासत को उचित सम्मान और नई पहचान दिलाई, क्योंकि हमारा मानना है कि सरदार पटेल का सम्मान, भारत का सम्मान है।



Amit Shah
@AmitShah

इसी वर्ष 31 मार्च को देश नक्सलमुक्त हो चुका है और अब 31 दिसंबर 2029 तक नशे से पूरी तरह मुक्त होगा। 'विकसित भारत' का पहला चरण नशामुक्त भारत ही है।



Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

A PROUD MOMENT FOR INDIA!🇮🇳

Our para-athletes have scripted history at the Asian Para Games, bringing home a record 114 🥇🥈🥉 and showcasing the extraordinary power of courage, perseverance and sporting talent.

Heartiest congratulations to every athlete who made the Tricolour soar high. Under the leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji, India's commitment to nurturing sporting talent is opening new horizons for our athletes to excel on the global stage.💪🔥



Kiren Rijiju @KirenRijiju ·

आज हमने Defence, Space और Nuclear Energy के संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमति बनाई है। इन सभी Strategic क्षेत्रों में हम पोलैंड की Companies को भारत के साथ Co-Development और Co-Production करने के लिए आमंत्रित करते हैं: माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी

#IndiaPolandFriendship



Arjun Ram Meghwal @arjunrammeghwal

देश की 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव मजबूत करने वाले सरदार पटेल जी का अदम्य साहस, दूरदर्शिता एवं राष्ट्रसेवा सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे।

भारत की एकता एवं अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की आ
सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

#SardarPatelJayanti #NationalUnityDay

प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- जब देश किसी संकट का सामना करता है तो वह खुशी मनाता है

जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा में ही जुटा रहूंगा : मोदी

संबोधन

भीलवाड़ी (गुजरात), एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वह अपनी अंतिम सांस तक देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। उनका यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कथित टिप्पणी के बाद आया है।

प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जब देश किसी संकट का सामना करता है तो वह खुशी मनाता है और पश्चिम दुनिया में जारी संघर्ष के बीच उर्वरकों तथा रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लोगों में घबराहट फैलाता है। मोदी ने कहा कि किसान, युवा और महिलाएं विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोगों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही है। दरअसल, पीएम मोदी गुजरात में बनासकांठा जिले के पेलेनी में 'भारत कैंसर इंडिया एंड रिसर्च सेंटर' का उद्घाटन करने और 14 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

पीएम-किसान की 21वीं किस्त जारी : इस दौरान पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त भी जारी की। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस किस्त के तहत 12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई।



रोड शो में गूंजा... 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पीएम मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री जब गुजरात के बनासकांठा में रोड शो के लिए निकले, तो सड़क किनारे खड़े लोग 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे' लिखी तख्तियां लहराते और नारे लगाते दिखे। दूसरी तरफ बूथों में गुजमगी अभिज शाह ने भी 2029 में मोदी के फिर प्रधानमंत्री बनने की बात कहकर रिएक्ट पर पलटवार किया। साथ ही कि खरगे के बयान पर भाजपा ने साफ़ा से लेकर चुनावी मंच तक आक्रामक जवाबी रणनीति अपना ली है।

> किसान, युवा और महिलाएं विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोगों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही है। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

किसानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, यह ध्यान रखा

किसानों की संवेदना करते हुए मोदी ने कहा कि वैश्विक बाजार में उर्वरकों और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की कीमतें में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इसका अतिरिक्त बोझ किसानों पर न पड़े। उन्होंने कहा, दुनियाभर में यूरिया की एक बोरी की कीमत 3,000 रुपये तक है, जबकि भारतीय किसानों को यह 300 रुपये से भी कम में मिलता है। किसानों को यूरिया का एक बोरा महज 300 में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अतिरिक्त बोझ खुद उठाया है।

सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी

मोदी ने कहा बीते कुछ वर्षों में देशभर के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए 50 लाख करोड़ से अधिक की राशि मिली है या उनकी इतनी बचत हुई है। दीसा में कहा, सरकार ने किसानों के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच उर्वरकों की 6करोड़ बोरियों से किसानों को बचाने के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

हुए मोदी ने कहा कि कुछ से पैदा हुई स्थिति से निपटने को पूरा देश एकजुट है, पर कुछ लोग अफवाहें फैलाकर जनता में घबराहट पैदा कर रहे हैं। मोदी ने आरोप लगाया, उन्होंने किसानों के बीच डर फैलाया कि उर्वरक उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने कृत्रिम कमी बताई और घबराहट का माहौल पैदा किया।

केंद्र के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, DA बढ़ा

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3% बढ़ोतरी की मंजूरी दी। यह बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी। इससे मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 60% की दर में 3% की बढ़ोतरी होगी ,ताकि बढ़ती कीमतों की भरपाई की जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए ये दिवाली का तोहफा बताया।



AI Image

3% की बढ़ोतरी की गई महंगाई भत्ते में

■ 10 हजार करोड़ का भार पड़ेगा सरकार के खजाने पर

■ 48.54 लाख कर्मी और 68.71 लाख पेंशनभोगी है



अश्विनी वैष्णव

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इन बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का कुल भार पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इस बढ़ोतरी से महंगाई इससे पहले सरकार ने अप्रैल में कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के लिए DR में 2 फीसदी का इजाफा किया था।

कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का नया सेंटर

मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2039-40 तक के लिए 'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' को मंजूरी दे दी है। 10,000 करोड़ की यह स्कीम भारत को वैश्विक कंटेनर निर्माण का नया केंद्र बनाने की दिशा में अहम पहल है। 13 साल की इस योजना के तहत पूंजी निवेश पर ब्याज सब्सिडी, टैरिफ एवं सर्टिफिकेशन, लैंड लीजिंग और परिचालन खर्च में सहायता दी जाएगी। इससे कंटेनर निर्माण में घरेलू क्षमता विकसित करने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। कंटेनर निर्माताओं को ब्याज सब्सिडी सहायता के लिए 859 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ग्राम स्वराज योजना को 7,395 करोड़

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए 7,395 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। वैष्णव ने इसे पहले से तय योजनाओं से हटकर स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण पर केंद्रित मॉडल की ओर बड़ा बदलाव बताया। कहा, 'यह एक बड़ा बदलाव है।' इससे 2.55 लाख पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख प्रतिनिधियों के साथ पंचायतों को सीधा लाभ मिलेगा।

12 साल में 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए: PM

■ भाषा, नई दिल्ली/रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व बैंक की उस रिपोर्ट की सराहना की है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने दुनिया में गरीबी में सबसे तेज गिरावट दर्ज करने वाले देशों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें विश्व बैंक का हवाला देते हुए बताया कि 2011 से 2023 के बीच 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। इस दौरान अत्यधिक गरीबी की दर में 90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह हर चार में से एक से अधिक भारतीय के स्तर से घटकर लगभग 38 में से एक रह गई।



नरेन्द्र मोदी

उन्होंने कहा, 'महज छह वर्षों में रोजगार के अवसरों में 13.4 करोड़ की वृद्धि हुई। असमानता में काफी कमी आई है।' मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के 26वें स्थापना दिवस पर कहा कि कभी माओवाद से प्रभावित रहे राज्य के इलाके अब शांति और विकास के केंद्र बन रहे हैं।

एकता दिवस परेड में प्रधानमंत्री मोदी बोले

सरदार पटेल के फैसलों ने देश को एकजुट किया

प्रधानमंत्री मोदी ने एकतानगर को दी 400 करोड़ रुपए की सौगात

पर्यटन स्थल होंगे विशेष तो आकर्षित होंगे लोग, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें देश की एकता, विविधता और सामूहिक शक्ति की झलक देखने को मिली। परेड में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव को प्रदर्शित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता को आकार देने और उसकी रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई। एकता हमें एक राष्ट्र के रूप

» आईआरसीटीसी होटल, रेलवेरिसेट व ट्रेनों टूरिज्म वाई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया

» पर्यटकों को मिलेगी बेहतर सुविधा



अन्य व्यवसायों में भी होगा लाभ

पीएम मोदी ने कहा कि इन पारंपरिकताओं से एकजुटता में एकीकृत परिस्थितियां कहने की उम्मीद है। होटल और पर्यटन सुविधाओं के संचालन से

लहराने का खास विकल्प मिलेगा

रेलवेरिसेट, ईको ट्रेल और समर्थ धाम का विकास

इन नई परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला

पीएम मोदी ने की 16 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की समीक्षा



नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को रेलवे, पीएम एकता मॉल और 'बल्क ड्रग पार्क' से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित की जा रही हैं और इनकी लागत 16,000 करोड़ रुपये से अधिक है। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में 'प्रगति' की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की। 'प्रगति' सूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी)-आधारित एक मल्टी-मॉडल मंच है, जिसका उद्देश्य सक्रिय शासन को बढ़ावा देना और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। बयान में कहा गया कि बैठक में आर्थिक विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें समय सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और समस्याओं के समय पर समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि 'पीएम एकता मॉल' स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराएं, कारीगरों की आजीविका को मजबूत करें और उनके उद्यमों को विस्तार देने में उनकी मदद करें। मोदी ने मॉल को पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे मॉल बड़ेगी, जिससे ग्रामीण उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। बयान में कहा गया कि मोदी ने मुख्य सचिवों द्वारा नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने और मॉल का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने पर जोर दिया। केंद्रीय बजट 2023-24 में 'पीएम एकता मॉल' स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) उत्पादों, भौगोलिक संकेत (जीआई) वाले उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं को बढ़ावा देना और उनकी बिक्री करना है। एकता मॉल में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक समर्पित स्थान का प्रावधान है, जहां वे अपने ओडीओपी उत्पादों का प्रदर्शन कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 'बल्क ड्रग पार्कों' की समीक्षा करते हुए आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए सक्रिय दवा तत्वों (एपीआई) और दवा बनाने में इस्तेमाल अन्य आवश्यक वस्तुओं के घरेलू स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस (एनसीसी) : 22 नवंबर

युवा शक्ति को सशक्त बनाता एनसीसी

एनसीसी एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के युवाओं को आत्मविश्वासी, अनुशासित, संवेदनशील और देश के प्रति समर्पित नागरिक बनाता है। देश में एनसीसी के नेटवर्क को मजबूती देने की कड़ी में बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। एनसीसी, एक ऐसा संगठन है जो भारत की युवाशक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर, सक्षम और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध नागरिक बनने का भरता है भाव...

“

एनसीसी से हमें स्कूल-कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं। इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। 'एनसीसी' युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

एनसीसी में हैं 20 लाख से अधिक कैडेट

- वर्ष 1948 में 20,000 कैडेटों की संख्या के साथ स्थापित एनसीसी, आज विश्व का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म वाला युवा संगठन है, जिसमें 20 लाख से अधिक कैडेट हैं।
- वर्ष 2014 से 2025 के बीच संगठन में 6 लाख कैडेटों की वृद्धि हुई है। वर्तमान में यह देश के 750 से अधिक जिलों में उपस्थिति है।



न्यू इंडिया समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 16-30 नवंबर, 2026
आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 4 नवंबर 2026, कुल पृष्ठ-46)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित